

करेंट अफेयर्स

राजस्थान

(संग्रह)



दिसंबर

2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान	4
● राजस्थान में फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण.....	4
● राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास.....	5
● जयपुर में निवेशक शिविर का आयोजन	5
● राजस्थान में बाल विवाह विरोधी अभियान.....	6
● राजस्थान में पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति	7
● राजस्थान में उन्नत खनिज अन्वेषण हेतु AI का उपयोग.....	9
● हिंदुस्तान जिंक द्वारा उत्तर भारत में पहला फॉस्फेट संयंत्र स्थापित	10
● अडॉप्ट ए टूरिज्म साइट इनिशिएटिव	11
● रक्षा मंत्री द्वारा वर्ष 1971 युद्ध के हीरो की प्रतिमा का अनावरण.....	12
● तपेदिक स्क्रीनिंग हेतु AI एक्स-रे	13
● RVCF द्वारा इंडिया ग्रोथ फंड लॉन्च	13
● कलानुभाव: दिल्ली में राजस्थान शिल्प प्रदर्शनी.....	14
● दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण	15
● राजस्थान के नागौर में किसान सम्मेलन	15
● राजस्थान में ई-स्वास्थ्य संवाद पहल	16
● ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को IT ट्रेनिंग	16
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स	18
● विश्व एड्स दिवस 2025	18
● वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025	20
● भारत IMP काउंसिल में पुनः निर्वाचित	21
● एयर मार्शल तेजबौर सिंह महानिदेशक (निरीक्षण एवं सुरक्षा) नियुक्त	22
● सैटेलाइट-लिंकड हेरॉन एमके II (UAVs)	23
● विवेक चतुर्वेदी CBIC प्रमुख नियुक्त	24
● ALIMCO का 53वाँ स्थापना दिवस.....	25
● संचार साथी ऐप.....	26
● असम दिवस.....	27
● नौसेना दिवस 2025	28
● ऑपरेशन सागर बंधु	29
● भारत-मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास	30

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



ज्ञानेश कुमार ने IDEA परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की	30
भारत की प्रथम पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना	31
खुदीराम बोस जयंती	32
अंटार्कटिका दिवस	33
BSF स्थापना दिवस	34
नागालैंड राज्य दिवस	36
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस	37
EARTH समिट 2025	37
हस्तशिल्प पुरस्कार	39
डॉ. अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस	39
मानव अधिकार दिवस	40
बंगलूरु में UNSW कैंपस	42
सशस्त्र सेना झंडा दिवस	44
बंगलूरु में नया रक्षा MRO हब	45
वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन (GELS) 2025	46
सी. राजगोपालाचारी जयंती	47
सुजलाम भारत ऐप	49
प्राडा द्वारा कोल्हापुरी डील साइन	49
प्रणब मुखर्जी की जयंती	50
भारत को जूनियर हॉकी में ऐतिहासिक कांस्य पदक	51
राज कुमार गोयल ने CIC पद की शपथ ली	52
भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन	53
परमाणु ऊर्जा रूपांतरण विधेयक, 2025	54
रक्षा संपदा दिवस का शताब्दी वर्ष समारोह	55
भारत और ADB के बीच विकास ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर	56
भू-स्थानिक मिशन पर राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यशाला	57
मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र	57
सहकार सारथी	58
नमस्ते योजना: सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों का सर्वेक्षण	58
आंध्र प्रदेश में व्हाइट स्पॉट डिजीज	59
नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट, 2025	60
नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन	60
किम्बर्ले प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा भारत	61
वीर बाल दिवस	62
अगरबत्ती के लिये नया BIS मानक	62
FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025	63
के-4 बैलिस्टिक मिसाइल	63
भारत टैक्सी पहल	64

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान

राजस्थान में फिरोज़पुर फीडर का पुनर्निर्माण

चर्चा में क्यों ?

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साधूवाली में फिरोज़पुर फीडर नहर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया, जो उत्तरी राजस्थान में **सिंचाई सुविधाओं** को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

- परियोजना के बारे में: यह परियोजना दूरस्थ कृषि क्षेत्रों में विश्वसनीय सिंचाई जल आपूर्ति सुनिश्चित करके किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- पुनर्निर्माण: 647 करोड़ रुपये की लागत से फीडर के पुनर्निर्माण का उद्देश्य **हरिके बैराज** से अधिशेष जल के मार्ग परिवर्तन में सुधार करना तथा **रबी और खरीफ फसलों** के लिये सिंचाई विश्वसनीयता को बढ़ाना है।
 - 300 करोड़ रुपये के अलग आवंटन से **बीकानेर नहर का जीर्णोद्धार** किया जाएगा, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ होगा और राज्य का सदियों पुराना नहर नेटवर्क मज़बूत होगा।
- स्वचालन: 695 करोड़ रुपये के निवेश से 3.14 लाख हेक्टेयर में सिंचाई को स्वचालित किया जाएगा, जिससे दक्षता बढ़ेगी, जल प्रवाह को विनियमित किया जाएगा और कमांड क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा।
- क्षमता वृद्धि: उन्नत फिरोज़पुर फीडर की वहन क्षमता 9,000 क्यूसेक से बढ़कर 13,842 क्यूसेक हो जाएगी, जिससे अतिरिक्त **मानसून जल का भंडारण संभव हो सकेगा**, जो अन्यथा पाकिस्तान की ओर बह जाता है।
- समय-सीमा: परियोजना के तहत **कंक्रीट लाइनिंग, रेगुलेटरों के पुनर्निर्माण** तथा **रेलवे क्रॉसिंग** की मरम्मत जैसे सभी प्रमुख कार्य अक्टूबर, 2027 तक पूर्ण करने की योजना बनाई गई है, ताकि यह समय-सीमा नहर के ऐतिहासिक उद्घाटन दिवस के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके।
- शताब्दी-वर्ष: 1,717 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं का शुभारंभ **गंग नहर की 100वीं वर्षगांठ** के अवसर पर किया गया है, जिसे मूलतः महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित किया गया था और जो राजस्थान के शुष्क जिलों के लिये जीवनरेखा है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **विरासत:** यह परियोजना महाराजा गंगा सिंह द्वारा 20वीं सदी के प्रारंभ में बीकानेर के लिये **सतलुज नदी** का पानी सुरक्षित करने के लिये किये गए निरंतर संघर्ष का सम्मान करती है, जिसमें कड़े राजनीतिक प्रतिरोध, तकनीकी संदेहों और **प्रथम विश्व युद्ध** के कारण हुई देरी के बावजूद भी उन्होंने यह कार्य पूर्ण किया।

राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

आतंकवाद-निरोध तथा शांति-स्थापना परिदृश्यों में अंतर-संचालनीयता को सशक्त बनाने हेतु भारत-मलेशिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास '**हरिमाउ शक्ति**' का पाँचवाँ संस्करण राजस्थान में शुरू हुआ।

मुख्य बिंदु

- ❖ **अभ्यास के बारे में:**
 - ⦿ यह **भारतीय सेना** तथा **मलेशियाई सेना** के मध्य आयोजित एक **द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास** है, जो वन क्षेत्रीय तथा आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित है।
 - ⦿ यह अभ्यास वर्ष **2012 में प्रारंभ** हुआ था तथा भारत की **एक्ट ईस्ट नीति** तथा वैश्विक शांति-स्थापना ढाँचे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और अधिक दृढ़ करता है।
- ❖ **सहभागी (2025):**
 - ⦿ भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट तथा मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन (Royal Malaysian Army) इस संस्करण में भाग ले रही हैं।
- ❖ **उद्देश्य और अधिदेश:**
 - ⦿ **संयुक्त राष्ट्र अध्याय VII** के अधिदेश के अंतर्गत उप-पारंपरिक अभियानों का संयुक्त पूर्वाभ्यास किया जाएगा, जिसमें **घेराबंदी/तलाशी अभियान, हेलीबोर्न ऑपरेशन** तथा हताहतों की निकासी जैसे आतंकवाद-रोधी अभ्यासों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
 - ⦿ **सेना मार्शल आर्ट्स रूटीन (AMAR), कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग** तथा योग भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।
 - ⦿ संयुक्त राष्ट्र अध्याय VII अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रवर्तन के लिये सैन्य/गैर-सैन्य कार्रवाइयों (प्रतिबंध, नाकाबंदी, सैन्य तैनाती) को अधिकृत करता है।
- ❖ **अन्य सैन्य अभ्यास:**
 - ⦿ **समुद्र लक्ष्मण** (द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास)
 - ⦿ **उदार शक्ति** (द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास)

जयपुर में निवेशक शिविर का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने **भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI)** तथा **बाजार अवसंरचना संस्थानों (MII)** के साथ साझेदारी में जयपुर में एक '**निवेशक शिविर**' आयोजित किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ **उद्देश्य:** शिविर ने छह से सात वर्षों से लंबित अघोषित लाभांश और अघोषित शेयरों की सीधी सुविधा प्रदान की, तत्काल **अपने ग्राहक को जानें (KYC)** तथा नामांकन अपडेट प्रदान किये एवं लंबित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) दावा मुद्दों का समाधान किया।
- ❖ **संपर्क-** पुणे, हैदराबाद और अमृतसर में सफल आयोजनों के बाद, जयपुर अगला मेज़बान शहर बना, जिसने निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) की **पारदर्शी, सुलभ एवं निवेशक-केंद्रित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र** के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA)

- ❖ भारत सरकार ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के प्रशासन की देख-रेख के लिये **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 125 के अंतर्गत 7 सितंबर, 2016 को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना की।
- ❖ प्राधिकरण निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि का प्रबंधन करने, दावा न किये गए लाभांश, शेयरों तथा परिपक्व जमा या डिबेंचर के लिये रिफंड की प्रक्रिया करने तथा निवेशकों के बीच **वित्तीय जागरूकता** को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी है।

राजस्थान में बाल विवाह विरोधी अभियान

चर्चा में क्यों ?

एक नागरिक समाज नेटवर्क ने राजस्थान के 38 उच्च-जोखिम वाले जिलों की पहचान की है, जहाँ पूरे वर्ष तक चलने वाले अभियान के माध्यम से **बाल विवाह को समाप्त** करने के लिये **सामुदायिक सक्रियता** और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- ❖ **पूर्व सफलता:** जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) नेटवर्क, 17 साझेदार संगठनों के साथ काम करते हुए, पिछले वर्ष राजस्थान में 22,480 बाल विवाहों को रोकने में सफल रहा।
- ❖ **सरकारी सहायता:** यह पहल राज्य सरकार के प्रयासों को पूरक करेगी, जिसमें **पंचायत स्तर के संसाधनों** का उपयोग करके दूर-दराज के गाँवों में जागरूकता अभियान का विस्तार किया जाएगा।
- ❖ **उच्च-प्रसार क्षेत्र:** चयनित जिलों को **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) 2019-21** के आँकड़ों के आधार पर उच्च-प्रसार क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ❖ **सामुदायिक सहभागिता:** JRC बाल विवाह को **बच्चों के विरुद्ध अपराध** बताते हुए, इसे सामूहिक रूप से समाप्त करने हेतु **सामुदायिक समूहों, धार्मिक नेताओं, पंचायतों तथा नागरिकों** की भागीदारी पर जोर देता है।
- ❖ **सहयोगात्मक कार्रवाई:** राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभागों के अधिकारियों को बाल-विवाह विरोधी अभियान को सक्रिय समर्थन एवं सुदृढ़ करने के लिये निर्देश दिया है।
- ❖ **राष्ट्रीय पहल:**
 - ❶ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** के अनुरूप वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के उद्देश्य से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



♦ राज्य सांख्यिकी:

- राजस्थान में बाल विवाह का कुल प्रचलन 25.4% है, जो राष्ट्रीय औसत 23.3% से थोड़ा अधिक है।
- चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में यह दर 40% से अधिक है, जबकि नौ जिले, जिनमें झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर और अलवर शामिल हैं, में यह दर 30% से अधिक है।
- अन्य नौ जिले 23%-29.9% सीमा में आते हैं, जो पूरे राज्य में व्यापक संवेदनशीलता को दर्शाता है।

बाल विवाह रोकने हेतु की पहलें:

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA)
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
- यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012
- चाइल्ड लाइन

राजस्थान में पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने **जल जीवन मिशन** के तहत नोनेरा तथा परवान-अकावड़ पेयजल परियोजनाओं के लिये कार्य आदेश जारी किये हैं, जिनकी कुल लागत 5,184 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

मुख्य बिंदु

- लाभांविता जिले: परियोजनाओं के पूर्ण होने पर कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारों जिलों के घरों को नियमित पेयजल की आपूर्ति प्राप्त होगी।
- नोनेरा परियोजना कवरेज: नोनेरा परियोजना कोटा और बूंदी के 749 गाँव और 6 कस्बों को जलापूर्ति करेगी, जिससे 1,13,287 परिवार लाभांविता होंगे।
- नोनेरा अवसंरचना: 1,661.14 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत वाली इस परियोजना में 1 इनटेक स्टेशन, 3 जल-शोधन संयंत्र, 14 भंडार, 137 ऊँची टंकियाँ तथा 4,560 किमी. से अधिक पाइपलाइन नेटवर्क शामिल है।
- परवान-अकावड़ कवरेज: इस परियोजना से 1,402 गाँवों को लाभ होगा, जिनमें बारों के 907, कोटा (सांगोद) के 184, झालावाड़ के 311 तथा 276 छोटे गाँव सम्मिलित हैं, जिससे कुल 1,52,437 परिवारों को लाभ प्राप्त होगा।
- परवान-अकावड़ अवसंरचना: 3,523.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति वाली इस परियोजना में 2 इनटेक स्टेशन, 2 शोधन संयंत्र, 41 भंडार, 276 ऊँची टंकियाँ तथा 10,000 किमी. से अधिक पाइपलाइनें शामिल हैं।
- समय-सीमा: दोनों परियोजनाओं को अगस्त, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत हर घर तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के राज्य लक्ष्य को समर्थन मिलेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



जल जीवन मिशन (JJM)

परिचय:

- 15 अगस्त, 2019 को प्रारंभ किया गया जल जीवन मिशन (JJM), प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 से बढ़ाकर वर्ष 2028 कर दिया गया है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है।

- यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य: (स्मरण सूत्र: TAP)

- T - प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लक्षित करना: सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध कराना।

- A - प्राथमिकता वाले क्षेत्र: गुणवत्ता-प्रभावित, अर्द्ध-शुष्क, सूखाग्रस्त, मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा संसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के अंतर्गत आने वाले ग्रामों को प्राथमिकता देना।

- P - सार्वजनिक स्थान: विद्यालय, आँगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत भवन तथा अन्य सामुदायिक स्थलों पर नलजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

राजस्थान में उन्नत खनिज अन्वेषण हेतु AI का उपयोग

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान **खनिज अन्वेषण** में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** तथा **मशीन लर्निंग (ML)** को लागू करने जा रहा है, जो राज्य के खनन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

AI मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण है, जिसे मनुष्यों की तरह सोचने और सीखने के लिये प्रोग्राम किया गया है, जो समस्या-समाधान, तर्क और नई जानकारी के अनुकूल होने में सक्षम है।

AI टाइमलाइन - प्रमुख परिवर्तन (Milestones)

- 1950s** का दशक: ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव; पहला AI प्रोग्राम विकसित
- 1956** डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ने "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" को मान्यता दी
- 1960s** का दशक: एलिजा चैटबॉट का निर्माण; प्रारंभिक न्यूरल नेटवर्क
- 1996** डीप ब्लू - एक शतरंज खेलने वाला प्रोग्राम (Chess-Playing Program)
- 2012** डीप लर्निंग ब्रेक थू इन इमेज रिकॉग्निशन
- 2014** जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN) का प्रस्ताव
- 2020** GPT-3 द्वारा उन्नत भाषा निर्माण का प्रदर्शन
- 2022** चैटजीपीटी लॉन्च हुआ, जो संवादात्मक AI को आम लोगों तक पहुँचाएगा
- 2023** जनरेटिव AI बूम; प्रमुख टेक कंपनियों ने AI मॉडल जारी किये



AI के अनुप्रयोग

- ⊕ **स्वास्थ्य सेवा:** व्यक्तिगत चिकित्सा
- ⊕ **वित्त:** एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग
- ⊕ **परिवहन:** ऑटोनोमस व्हीकल
- ⊕ **विपणन और ग्राहक सेवा:** टार्गेटेड एडवर्टाइजिंग चैटबॉट
- ⊕ **शिक्षा:** अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम
- ⊕ **कृषि:** फसल निगरानी
- ⊕ **साइबर सुरक्षा:** खतरे का पता लगाना
- ⊕ **ऊर्जा:** स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन, खपत पूर्वानुमान

चिंताएँ

- ⊕ डीपफेक और गलत सूचना
- ⊕ एल्गोरिदमिक बायस
- ⊕ ऑटोमेशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट
- ⊕ गोपनीयता के मुद्दे
- ⊕ डेटा ऑनरशिप और लायबिलिटी इश्यु
- ⊕ एथिकल डिजीजन-मैकिंग कॉम्प्लेक्स

AI विनियमन

- ⊕ **AI पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) 2020 में प्रारंभ हुई**
- ⊕ **ब्लेचली घोषणा (2023):** AI पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना
- ⊕ **G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (2023):**
- ⊕ AI पर G7 हिरोशिमा (2023) प्रोसेस

भारत और AI

- ⊕ **AI 201 के लिये राष्ट्रीय रणनीति**
- ⊕ **AI फॉर ऑल:** स्व-शिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम
- ⊕ भारत द्वारा आयोजित **GPAI शिखर सम्मेलन 2023**
- ⊕ **इंडिया AI मिशन 2024**
- ⊕ **US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (USIAI) पहल:** महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI सहयोग
- ⊕ **AIRAWAT** (AI रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज सेपरिप्यूजन प्लेटफॉर्म) सुपरकंप्यूटर

प्रमुख AI प्रौद्योगिकियाँ



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- समझौते: प्रवासी राजस्थान दिवस के दौरान दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाएंगे, एक IIT हैदराबाद के साथ और दूसरा IIT ISM धनबाद के साथ।
- राष्ट्रीय संरक्षण: यह पहल महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज में सुधार करके आत्मनिर्भर भारत तथा डिजिटल इंडिया जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का समर्थन करती है।
- डेटा सहयोग: RSMET और IIT हैदराबाद के बीच एक आशय-पत्र के माध्यम से डेटा का आदान-प्रदान तथा सहयोगात्मक अनुसंधान संभव होगा।
- खनन अपशिष्ट अध्ययन: IIT ISM धनबाद के साथ साझेदारी का उद्देश्य राजस्थान में खनन अपशिष्टों और अवशेषों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है।
- डेटासेट एकीकरण: खनिज-समृद्ध क्षेत्रों की पहचान करने के लिये 39 जिलों से प्राप्त भू-वैज्ञानिक, भू-रासायनिक, भू-भौतिकीय, रिमोट सेंसिंग और उपग्रह डेटासेट को संयोजित किया जाएगा।
- लक्षित खनिज: अन्वेषण ताँबा, ग्रेफाइट, जस्ता, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों पर केंद्रित होगा।
- परियोजना की समय-सीमा: IIT हैदराबाद के साथ यह सहयोग 18 महीनों में चार चरणों में पूरा किया जाएगा, जिससे राज्य के लिये खनिज विकास का रोडमैप तैयार होगा।
- चिह्नित डंप: विभाग ने एक वर्षीय IIT ISM धनबाद परियोजना के तहत मूल्यांकन के लिये 80 खदान डंप का चयन किया है, जिसमें मानचित्रण, नमूनाकरण, निष्कर्षण अध्ययन और खनिज विश्लेषण शामिल हैं।
- राष्ट्रीय महत्व: रणनीतिक खनिजों की बढ़ती घरेलू और वैश्विक मांग के कारण, राजस्थान भारत के महत्वपूर्ण खनिज मिशन में एक मुख्य भूमिका निभाता है।

हिंदुस्तान ज़िंक द्वारा उत्तर भारत में पहला फॉस्फेट संयंत्र स्थापित

चर्चा में क्यों ?

हिंदुस्तान ज़िंक चित्तौड़गढ़ में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है, जो राजस्थान तथा उत्तर भारत में पहला फॉस्फेट संयंत्र होगा।

- साथ ही, लघु तथा मध्यम ज़िंक विनिर्माण उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक ज़िंक इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल पार्क भी विकसित किया जा रहा है, जो MSME क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा और संसाधन उपलब्ध कराएगा।

मुख्य बिंदु

- परिचय: चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा यह संयंत्र डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटेशियम (NPK) तथा अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट का उत्पादन करेगा, जो फसल-वृद्धि के लिये अत्यावश्यक माने जाते हैं।
- उद्देश्य: इस सुविधा का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान सहित उत्तर भारत में उर्वरक-आपूर्ति की कमी को दूर करना तथा आयात और लंबी दूरी के परिवहन पर निर्भरता को न्यूनतम करना है।
- निवेश: हिंदुस्तान ज़िंक इस उर्वरक संयंत्र में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा संयंत्र आगामी तीन महीनों में परिचालन के लिये तैयार हो जाएगा।
- उत्पादन क्षमता: इस संयंत्र की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता एक मिलियन टन होगी, जिससे कृषि के लिये आवश्यक उर्वरकों का उत्पादन होगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **क्षेत्रीय प्रभाव:** यह संयंत्र न केवल चित्तौड़गढ़, बल्कि राजस्थान के अन्य जिलों तथा पड़ोसी राज्यों को भी उर्वरक-आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
- ❖ **कृषि विकास:** फॉस्फेट-आधारित उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता क्षेत्रीय फसल-उत्पादकता में वृद्धि करेगी और कृषि-विकास को गति प्रदान करेगी।
- ❖ **आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन:** घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देकर यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को सुदृढ़ बनाती है।
- ❖ **रोजगार सृजन:** संयंत्र के संचालन से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ प्राप्त होगा।

अडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट इनिशिएटिव

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के तहत पर्यटन तंत्र को आधुनिक बनाने के लिये “अडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट” पहल शुरू कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ❖ **योजना का उद्देश्य:** इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र के अभिकर्ताओं, स्थानीय समुदायों और पर्यटन संबंधी हितधारकों को विरासत तथा पर्यावरण-पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार, प्रबंधन एवं संचालन के लिये आमंत्रित करना है।
- ❖ **सतत मॉडल:** इसे प्रमुख पर्यटन स्थलों, जिनमें **मंदिर और पर्यावरण-पर्यटन स्थल** शामिल हैं, के रखरखाव के लिये एक **सतत, राजस्व-समर्थित मॉडल** का निर्माण करने तथा सरकार पर बोझ कम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- ❖ **गोद लेने की अवधि:** भागीदार **कम-से-कम पाँच वर्षों की अवधि** के लिये स्थलों को गोद ले सकते हैं और आगंतुक सुविधाओं के विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी का वहन कर सकते हैं।
- ❖ **वाणिज्यिक गतिविधियाँ:** यह मॉडल स्व रखरखाव के लिये धन एकत्रित करने हेतु अपनाए गए क्षेत्रों में **वाणिज्यिक और अर्द्ध-वाणिज्यिक गतिविधियों को शुरू करने** की अनुमति देता है।
- ❖ **स्थानीय एकीकरण:** साझेदार स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प, कला और पारंपरिक उत्पादों के साथ **शॉपिंग आर्केड** स्थापित करेंगे, जिससे स्थानीय कारीगरों को लाभ होगा तथा आगंतुकों का अनुभव बेहतर होगा।
- ❖ **आजीविका सृजन:** इस योजना से राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थानीय कारीगरों के लिये **आजीविका के नए अवसरों के सृजन की उम्मीद** है।
- ❖ **पर्यटन संवर्द्धन:** यह नीति साझेदारों को कैफेटेरिया, रेस्तरां और चुनिंदा स्मारिका दुकानों (Souvenir Shops) जैसी सुविधाओं के साथ **पर्यटन मूल्य श्रृंखला में सुधार करने** के लिये प्रोत्साहित करती है।
- ❖ **नाइट टूरिज़्म:** विभाग उच्च-आवागमन वाले स्थलों पर रात्रिकालीन पर्यटन और राजस्व बढ़ाने के लिये अनुकूलनीय **संचालन समय**, जिसमें संभावित रूप से पूरी रात खुला रखने का विकल्प भी शामिल है, पर विचार कर रहा है।
- ❖ **भविष्य के दिशा-निर्देश:** राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के कार्यान्वयन के अंतर्गत, **पातः स्थलों और अनुमत सुविधाओं की सूची** सहित विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किये जाएंगे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



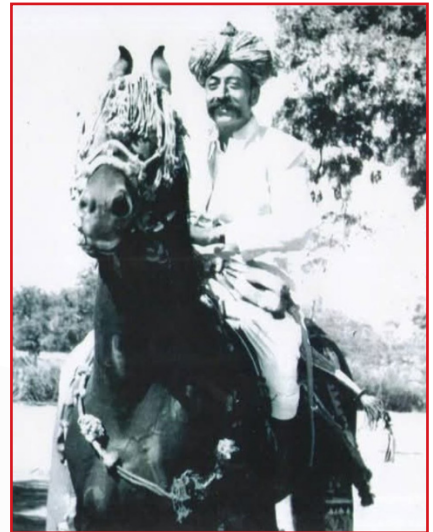
रक्षा मंत्री द्वारा वर्ष 1971 युद्ध के हीरो की प्रतिमा का अनावरण

चर्चा में क्यों ?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 दिसंबर, 2025 को राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के बखासर गाँव में ठाकुर बलवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

मुख्य बिंदु

- ❖ **युद्ध के नायक:** ठाकुर बलवंत सिंह ने वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, विशेष रूप से चाचरो की लड़ाई के दौरान, **भारतीय सेना** का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ❖ **योगदान:** उनके स्थानीय ज्ञान और बहादुरी ने भारतीय सेना को सिंध में चाचरो पर कब्जा करने और **पाकिस्तानी सेना को वापस लौटने** में मदद की।
- ❖ **मान्यता:** उनके योगदान के सम्मान में, सिंह के खिलाफ आपराधिक मामले वापस ले लिये गए और उन्हें **दो अखिल भारतीय हथियार लाइसेंस प्रदान** किये गए।
- ❖ **विरासत:** ठाकुर बलवंत सिंह का **देहांत वर्ष 1991** में हुआ था, उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिये उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है।



शिमला समझौता, 1972

- ❖ यह वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद 2 जुलाई, 1972 को हस्ताक्षरित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप **बांग्लादेश का गठन** हुआ।
- ❖ इसे संबंधों को सामान्य करने और शांति स्थापित करने के लिये भारत की **प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी** तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा वार्ताक्रम के माध्यम से तैयार किया गया था।
- ❖ **उद्देश्य:**
 - कश्मीर मुद्दे का द्विपक्षीय समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीयकरण को रोकना।
 - नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार करना।
 - भारत ने पाकिस्तान में और अधिक असंतोष को रोकने के लिये सीज फायर लाइन को स्थायी सीमा नहीं बनाया।
- ❖ **प्रमुख प्रावधान:**
 - **संघर्ष का समाधान:** मुद्दों का द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाएगा।
 - **नियंत्रण रेखा (LoC):** दोनों देशों ने वर्ष 1971 युद्ध के बाद स्थापित LoC का सम्मान करने तथा उसकी स्थिति को एकतरफा न बदलने पर सहमति जताई।
 - **सैनिकों की वापसी:** दोनों देशों की सेनाएँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने-अपने क्षेत्रों में लौटेंगी।
 - **भविष्य की कूटनीति:** संवाद जारी रखने और युद्धबंदियों की वापसी के प्रावधान शामिल थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



तपेदिक स्क्रीनिंग हेतु AI एक्स-रे

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य विभाग ने **क्षय रोग (Tuberculosis)** के निदान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 29 उन्नत पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों को राज्य में स्थापित किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **प्रौद्योगिकी:** पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** आधारित प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ गाँवों सहित संदिग्ध तपेदिक मामलों की त्वरित पहचान में सक्षम हैं।
- ❖ **उद्देश्य:** इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ समुदायों में तपेदिक के शीघ्र निदान, उपचार तथा प्रभावी प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।
- ❖ **प्राथमिकता:** ईट-भट्टों, निर्माण स्थलों, खनन क्षेत्रों, जेलों, छात्रावासों, झुग्गी-झोपड़ियों और अन्य सामूहिक आवासों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को तपेदिक जाँच के लिये चिह्नित किया गया।
- ❖ **दृष्टिकोण:** स्वास्थ्य विभाग ने तपेदिक के निदान और उपचार में होने वाली देरी को कम करने के लिये सक्रिय केस फाइंडिंग को एक लागत-प्रभावी रणनीति के रूप में अपनाया।
- ❖ **अवसंरचना:** इस पहल के माध्यम से **सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं** में मौजूद प्रमुख कमियों, जैसे- **एक्स-रे उपकरणों की कमी और प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट की कमी**, को दूर करने का प्रयास किया गया।
- ❖ **स्क्रीनिंग:** संदिग्ध तपेदिक मामलों की पहचान हेतु **कंप्यूटर-सहायता प्राप्त पहचान** से युक्त उच्च-संवेदनशील डिजिटल चेस्ट एक्स-रे स्क्रीनिंग को अपनाया गया।
- ❖ **निदान:** स्क्रीनिंग में चिह्नित व्यक्तियों को त्वरित पुष्टिकरण निदान तथा उपचार-पूर्व अनुवर्ती कार्रवाई में चूक को कम करने के लिये एक्सपर्ट आणविक परीक्षण से जोड़ा गया।
- ❖ **स्थापना:** राजस्थान के 29 जिलों में **पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें स्थापित की गईं**। हाल ही में संचालित स्क्रीनिंग अभियान में लगभग 160 लाख की संवेदनशील आबादी में से 2.3 लाख व्यक्तियों में तपेदिक के लक्षण पाए गए।
- ❖ **स्थिति:** राजस्थान में तपेदिक का प्रकोप अत्यधिक है, जहाँ वर्ष 2024 में 1.7 लाख से अधिक मामले दर्ज किये गए, जबकि जून 2025 तक 89,132 मामले सामने आए।
- ❖ **लक्ष्य निर्धारण:** स्वास्थ्य विभाग ने **HIV/एड्स** से पीड़ित व्यक्तियों, **मधुमेह** रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, कुपोषित व्यक्तियों तथा तपेदिक से उबर रहे लोगों जैसे उच्च जोखिम समूहों की जाँच के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त एक्स-रे मशीनों के उपयोग की योजना बनाई है।

RVCF द्वारा इंडिया ग्रोथ फंड लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान **वेंचर कैपिटल फंड** ने 150 करोड़ रुपये के कोष और 100 करोड़ रुपये के ग्रीन शू विकल्प के साथ अपना चौथा फंड, **इंडिया ग्रोथ फंड IV** लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **उद्देश्य:** इस फंड को ऐसे प्री-सीरीज़ ए और सीरीज़ ए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिये विकसित किया गया था, जिनके पास स्केलेबल बिजनेस मॉडल, सुदृढ़ रोज़गार सृजन क्षमता तथा महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ क्षेत्र: प्रमुख निवेश क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन शामिल हैं।
- ❖ समर्थन: पूंजी के अलावा, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड स्टार्टअप को स्थायी रूप से आगे बढ़ने में मदद करने के लिये रणनीतिक मार्गदर्शन, शासन संबंधी सहायता और उद्योग नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करेगा।
- ❖ दृष्टिकोण: फंड, राजस्थान सरकार की नवाचार-आधारित विकास दृष्टि और स्व-संवर्धित स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है।
- ❖ पारंपरिक योगदान: 23 वर्षों से अधिक के संचालन के साथ, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड ने 44 निवेश किये हैं, जो मुख्य रूप से प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों तथा **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों** का समर्थन करते हैं।
- ❖ प्रतिफल: पहले के दो फंडों को सकारात्मक प्रतिफल के साथ पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, जबकि तीसरा फंड विनिवेश के अधीन है और निवेशित राशि के लगभग दोगुने प्रतिफल की संभावना है।
- ❖ प्रभाव: कुछ चयनित निवेशों में 20 गुना से अधिक रिटर्न प्राप्त हुआ, पोर्टफोलियो की चार कंपनियों को सार्वजनिक लिस्टिंग प्राप्त हुई और निवेशित उद्यमों ने 10 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की तथा 10,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए।
- ❖ समावेशिता: वित्त पोषित उद्यमों में से लगभग 66% की स्थापना पहली बार उद्यम करने वाले उद्यमियों द्वारा की गई थी और लगभग एक तिहाई में महिला संस्थापक थीं, जो फंड के समावेशी विकास दृष्टिकोण को उजागर करती है।

वेंचर कैपिटल फंड

- ❖ वेंचर कैपिटल फंड निवेश के ऐसे साधन हैं जो निवेशकों को स्टार्ट-अप तथा छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों में पैसा लगाने की अनुमति देते हैं।
- ❖ ये फंड मुख्य रूप से उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें उच्च विकास क्षमता और पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने की क्षमता होती है।
- ❖ **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड** (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के तहत, वेंचर कैपिटल फंड को श्रेणी I वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कलानुभाव: दिल्ली में राजस्थान शिल्प प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों ?

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के द कुंज में आयोजित कलानुभाव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आजीविका कार्यक्रमों के तहत विकसित राजस्थान के **हस्तशिल्प** नवाचारों को उजागर किया गया।

मुख्य बिंदु

- ❖ मुख्य आकर्षण: कलानुभाव प्रदर्शनी में राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत विकसित प्रमुख **हस्तशिल्प, हथकरघा**, कारीगरों द्वारा किये गए नवाचार तथा डिज़ाइन पंजीकृत उत्पाद प्रदर्शित किये गए हैं।
- ❖ स्थान: यह कार्यक्रम नई दिल्ली के द कुंज में आयोजित किया गया, जो कारीगरों को अपनी कृतियों को प्रदर्शित करने का एक विशेष मंच प्रदान करता है।
- ❖ उद्देश्य: प्रदर्शनी का उद्देश्य कारीगरों को सशक्त बनाना, उनके उत्पादों की बाज़ार तक पहुँच बढ़ाना और भारत के शिल्प क्षेत्र को गाँवों से वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचाना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल: जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर (JCKIC), कलानुभाव.इन और **AR/VR टूल्स** जैसे विज्ञान-प्रौद्योगिकी-सक्षम हस्तक्षेपों के माध्यम से कारीगरों की आजीविका को सशक्त करने, डिजाइन पंजीकरण को बढ़ावा देने तथा **GI समर्थन** प्रदान करने पर केंद्रित है।
- ❖ राष्ट्रीय प्राथमिकता संरक्षण: यह प्रदर्शनी भारत में क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने और कारीगर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये समन्वित विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार प्रयासों का सहयोग करती है।

दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण

चर्चा में क्यों ?

भारत ने अपनी दूसरी **अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण पहल** के तहत मध्य प्रदेश के **पेंच टाइगर रिजर्व** से राजस्थान के **रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व** में एक बाघिन का स्थानांतरण किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **अंतर्राज्यीय पुनर्वास:** तीन वर्षीय टीग्रेस PN-224 बाघिन को मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से हवाई जहाज द्वारा राजस्थान भेजा गया।
- ❖ **महत्त्व:** यह पहल आनुवंशिक विविधता को सुदृढ़ करने, बाघ संख्या की स्थिरता में सुधार करने और राजस्थान में बाघ आवास को सुदृढ़ करने के **वन्यजीव संरक्षण उपायों** का हिस्सा है।
- ❖ **अंतर्राज्यीय सहयोग:** भारत में यह बाघों का दूसरा अंतर्राज्यीय स्थानांतरण है, जो राज्य वन विभाग और **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** के बीच प्रभावी समन्वय को दर्शाता है।
- ❖ **पहला स्थानांतरण:** भारत में पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण वर्ष 2018 में किया गया था, जब दो बाघों (महावीर और सुंदरी) को मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया।
- ❖ **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):** यह **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत वर्ष 2005 में स्थापित भारत का सर्वोच्च बाघ संरक्षण निकाय है।
- ❖ **रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व:** यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है और वर्ष 2021 में बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। यह रणथंभौर तथा **मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व** के मध्य स्थित है।

राजस्थान के नागौर में किसान सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में आयोजित **किसान सम्मेलन** में भाग लिया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **स्थान:** यह कार्यक्रम राजस्थान के नागौर जिले की मेड़ता सिटी में आयोजित किया गया।
- ❖ **वित्तीय एवं विकास सहायता:** किसानों, दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीण परिवारों के लिये ग्रामीण आवास एवं आजीविका संवर्द्धन हेतु महत्वपूर्ण सहायता की घोषणा की गई।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ अवसंरचना संबंधी पहल: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ग्रामीण सड़क संपर्क पर विशेष ध्यान दिया गया।
- ❖ सरकारी योजनाएँ: सम्मेलन में फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), रोजगार गारंटी कार्यक्रम और व्यापक ग्रामीण विकास पहलों पर प्रकाश डाला गया।
- ❖ महत्त्व: इस आयोजन ने राजस्थान में ग्रामीण विकास, किसान कल्याण और आजीविका सुदृढ़ीकरण की केंद्र की प्रतिबद्धता को दृढ़ किया।

राजस्थान में ई-स्वास्थ्य संवाद पहल

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने 'ई-स्वास्थ्य संवाद' नामक एक डिजिटल स्वास्थ्य संचार पहल शुरू की।

मुख्य बिंदु

- ❖ उद्देश्य: राज्य की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में शासन, पारदर्शिता तथा समन्वय को सुदृढ़ करना।
- ❖ नेतृत्व: यह पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आरंभ की गई।
- ❖ संचालन विधि: संवाद सत्र सप्ताह में दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किये जाएंगे।
 - सत्र दो चरणों में आयोजित होंगे- पहला वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग प्रमुखों के साथ तथा दूसरा विस्तृत हितधारकों एवं जनता के साथ।
- ❖ जवाबदेही: अधिकारियों को 72 घंटों के भीतर किये गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को IT ट्रेनिंग

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और नवनियुक्त पर्यवेक्षकों को IT प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपनी प्रौद्योगिकी-सक्षम ज़िम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें, विशेषकर मोबाइल-आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से निगरानी से जुड़े कार्यों में।

प्रमुख बिंदु

- ❖ मंत्री की घोषणा: महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने एकीकृत बाल विकास सेवा निदेशालय की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की।
- ❖ नियमित प्रशिक्षण पर ज़ोर: मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये आँगनवाड़ी सहायकों, कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों के लिये नियमित IT-आधारित प्रशिक्षण के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
- ❖ आँगनवाड़ी केंद्र का विकास: अधिकारियों को आँगनवाड़ी केंद्रों के विकास में तेजी लाने का निर्देश दिया गया, जिसमें शौचालय, पेयजल और विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- ❖ सरकारी प्रतिबद्धता: राज्य सरकार आँगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने और समग्र विकास के लिये प्रतिबद्ध है ताकि समुदाय को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



ICDS योजना और आँगनवाड़ी

- ❖ **परिचय:** भारत में ICDS योजना 2 अक्तूबर, 1975 को प्रारंभ की गई थी। इसका नाम बदलकर आँगनवाड़ी सेवाएँ कर दिया गया और अब ये सेवाएँ सक्षम आँगनवाड़ी तथा **पोषण 2.0** के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं।
- 🌀 यह एक **केंद्रीय प्रायोजित योजना** है जिसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को प्रारंभिक **बाल देखभाल एवं विकास सेवाएँ प्रदान** करना है। यह कार्य आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) और सहायिकाओं (AWH) के बड़े नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है।
- ❖ **आँगनवाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:** ये सेवाएँ देश भर में आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से **सभी पात्र लाभार्थियों**, अर्थात् 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के **बच्चों**, **गर्भवती महिलाओं** और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान की जाती हैं।
- 🌀 इनमें से तीन सेवाएँ, अर्थात् **टीकाकरण**, **स्वास्थ्य संबंधी जाँच** तथा **रेफरल सेवाएँ**, स्वास्थ्य से संबंधित हैं एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
- ❖ **आँगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी:** ICT प्लेटफॉर्म **पोषण ट्रैकर** को देश भर में आँगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी पर वास्तविक समय के डेटा को एकत्रित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- 🌀 यह **आँगनवाड़ी केंद्र (AWC)** की गतिविधियों, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और लाभार्थियों के संपूर्ण प्रबंधन के 360 डिग्री का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

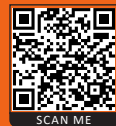


दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

विश्व एड्स दिवस 2025

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व एड्स दिवस 2025 के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर वे HIV रोकथाम, उपचार और कलंक उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही, एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की दिशा में प्रगति को गति देने के लिये नए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (**NACO**) बहु-माध्यम अभियानों का शुभारंभ किया।

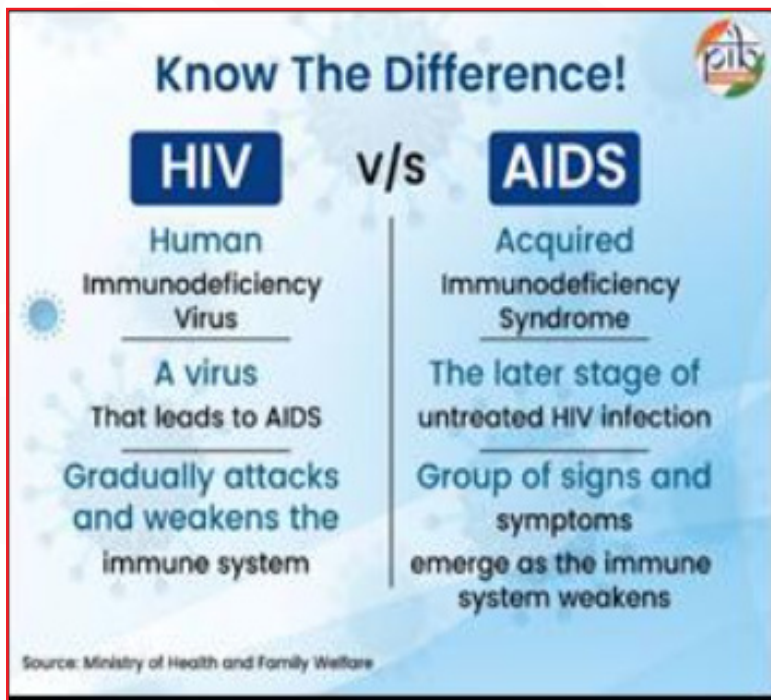
मुख्य बिंदु

विश्व एड्स दिवस

❖ **परिचय:** विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को HIV/AIDS महामारी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, HIV संबंधित बीमारियों से मृत लोगों को याद करने और **HIV/AIDS** के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों का समर्थन करने के लिये मनाया जाने वाला एक वैश्विक अवलोकन है।

❖ इसे पहली बार वर्ष 1988 में **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा चिह्नित किया गया था और तब से यह सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों के लिये इस रोग के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट होने का एक मंच बन गया है।

❖ **विषय:** इस वर्ष की थीम, “Overcoming disruption, transforming the AIDS response अर्थात अवरोधों को पार करना, एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करना”, अतीत की उपलब्धियों की रक्षा करने के साथ-साथ HIV सेवाओं को अधिक समुत्थानशील, न्यायसंगत और समुदाय-संचालित बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



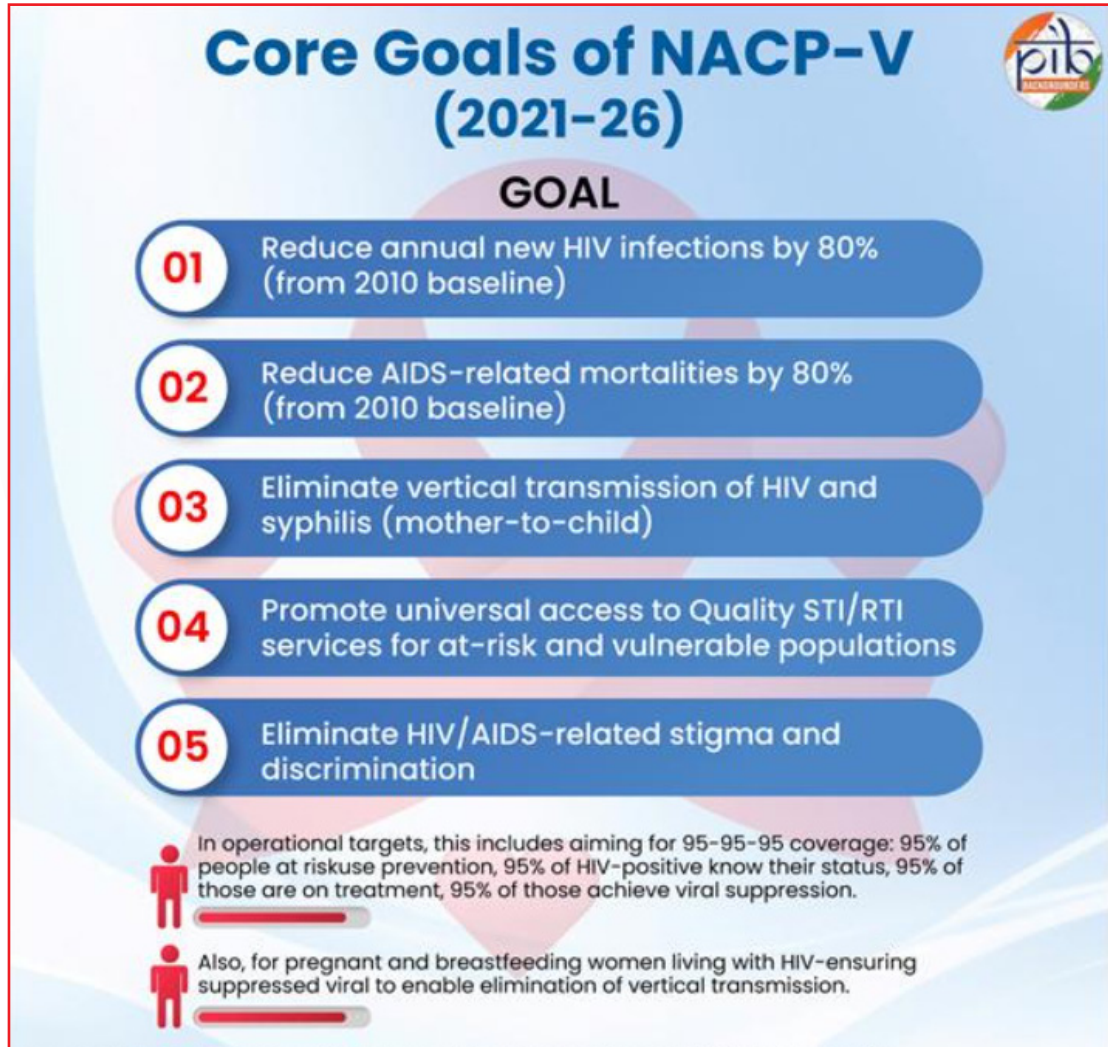
दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ♦ **भारत में अवलोकन:** भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान, सामुदायिक पहुँच गतिविधियों और नवीनीकृत सरकारी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाता है।

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस

- ♦ **परिचय:** HIV एक ऐसा वायरस है जो **CD4 कोशिकाओं** (श्वेत रक्त कोशिकाओं) पर हमला करके प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुँचाता है। यदि इसका उपचार न किया जाए, तो यह **एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम)** का कारण बन सकता है, जिससे शरीर संक्रमणों और कैंसर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **संचरण (ट्रांसमिशन):** HIV संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों जैसे- रक्त, वीर्य, स्तन दूध और योनि स्राव के सीधे संपर्क से फैलता है। यह असुरक्षित यौन संबंध, टैटू बनवाने तथा सुइयों साझा करने के माध्यम से भी फैल सकता है। यह सामान्य दैनिक संपर्क (जैसे- हाथ मिलाना, गले मिलना, एक साथ भोजन करना, मच्छर के काटने आदि) से नहीं फैलता है।
- ❖ **लक्षण: प्रारंभिक अवस्था** (बुखार, चकत्ते), **बाद की अवस्था** (सूजी हुई लिम्फ नोड्स, वजन कम होना, दस्त) और **गंभीर अवस्था** (तपेदिक, मस्तिष्कावरण शोथ, कैंसर (जैसे लिंफोमा))।
- ❖ **जोखिम कारक:** कई यौन साथी होना या यौन संचारित संक्रमण (STI) होना, असुरक्षित रक्त आधान।
- ❖ **निदान:** समान दिन के परिणामों के लिये त्वरित नैदानिक परीक्षण, स्व-परीक्षण किट और पुष्टिकरण वायरोलॉजिकल परीक्षण।
- ❖ **रोकथाम:** नियमित HIV परीक्षण, STI जाँच, सुरक्षित रक्त आधान और टैटू के लिये बंधीकृत सुइयों का उपयोग करना रोकथाम हेतु आवश्यक है।
- ❖ **उपचार:** HIV का कोई उपचार नहीं है, **एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART)** वायरस को नियंत्रित करने में सहायता करती है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये ART को जीवन भर प्रतिदिन लेना आवश्यक होता है।
- ❖ **उन्नत HIV रोग (AHD):** WHO AHD को $CD4 < 200$ कोशिकाएँ/मिमी³ के रूप में परिभाषित करता है। AHD वाले लोगों की मृत्यु का उच्च जोखिम होता है, यहाँ तक कि ART शुरू करने के बाद भी।
- ❖ **वैश्विक प्रतिक्रिया:** वर्ष 2030 तक HIV महामारी को समाप्त करना (संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3.3)।
- ❖ **भारत की प्रगति:** भारत HIV अनुमान 2023 के अनुसार, 2.5 मिलियन लोग HIV के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें 0.2% वयस्क प्रसार है। वर्ष 2010 के बाद से नए संक्रमणों में 44% की गिरावट आई है, जो वैश्विक 39% गिरावट से अधिक है।
 - ⦿ HIV/AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 HIV के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
 - ⦿ **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)**, जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था, भारत में HIV/AIDS के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य आधार बना हुआ है।

वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025

चर्चा में क्यों ?

भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में अपनी पहली भागीदारी में 29 देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 8वीं रैंक प्राप्त करके वैश्विक कौशल मंच पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** ताइपे, ताइवान में 27-29 नवंबर, 2025 को नानगंग प्रदर्शनी केंद्र में तीसरी वर्ल्डस्किल्स एशिया प्रतियोगिता की मेजबानी की गई। इस आयोजन ने शिक्षा, आर्थिक विकास, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये 29 एशियाई सदस्य तथा अतिथि देशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ लाया।
- ❖ **भागीदारी:** भारतीय दल में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के नेतृत्व में 21 विशेषज्ञों के समर्थन से 21 कौशल श्रेणियों में 23 प्रतियोगी शामिल थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **पदक तालिका:** भारत ने 1 रजत, 2 कांस्य पदक और 3 उत्कृष्टता पदक (मेडलियन फॉर एक्सीलेंस) प्राप्त किये। इनमें पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी, रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन, वेब टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसे कौशल क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन शामिल रहे।
- ❖ **महिलाओं की उपलब्धियाँ:** महिला प्रतियोगियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिससे पदक तालिका में महत्वपूर्ण योगदान मिला। उन्होंने गैर-पारंपरिक कौशल क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की और भारतीय प्रतिभागियों में सर्वाधिक समग्र अंक प्राप्त किये।
- ❖ **प्रशिक्षण एवं तैयारी:** प्रतियोगियों का चयन इंडिया स्किल्स नेशनल कॉम्पिटिशन 2024 के माध्यम से किया गया था और उन्होंने सेक्टर स्किल काउंसिल्स, शैक्षणिक संस्थानों एवं वैश्विक विशेषज्ञों के समर्थन से उद्योग-नेतृत्व वाले महीनों के गहन प्रशिक्षण से गुजरकर विश्व-स्तरीय तत्परता सुनिश्चित की।
- ❖ **महत्त्व एवं प्रभाव:** भारत का मजबूत पदार्पण वैश्विक कौशल प्रतिभा के केंद्र के रूप में देश की बढ़ती स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। यह देश के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती को दर्शाता है और युवा उत्कृष्टता, मजबूत प्रशिक्षण ढाँचे तथा समर्पित राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाता है।



भारत IMP काउंसिल में पुनः निर्वाचित

चर्चा में क्यों ?

भारत को वर्ष 2026-27 के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) काउंसिल में श्रेणी B के अंतर्गत सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित किया गया है, जिससे वैश्विक समुद्री मामलों में इसकी नेतृत्वकारी भूमिका की पुष्टि होती है।

- ❖ यह पुनर्निर्वाचन इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 की सफल मेजबानी के बाद हुआ है जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रमुख बिंदु

- ♦ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाने तथा जहाजों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपाय करने हेतु उत्तरदायी है।
- ♦ यह विधिक मामलों में भी शामिल है, जिसमें दायित्व और मुआवजे के मुद्दे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की सुविधा भी शामिल है।
- ♦ इसकी स्थापना 6 मार्च, 1948 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंगीकृत किये गए एक अभिसमय के माध्यम से की गई थी तथा इसकी पहली बैठक जनवरी, 1959 में हुई थी।
- ♦ IMO काउंसिल: काउंसिल IMO का कार्यकारी अंग है और सभा के अधीन संगठन के कार्यों की देख-रेख हेतु उत्तरदायी है।
- ♦ काउंसिल 40 सदस्य देशों से बनी है, जिन्हें सभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिये चुना जाता है।
- ♦ निर्वाचन परिणाम:
- ♦ लंदन में 34वीं IMO असेंबली के दौरान हुए चुनावों में भारत को 169 वैध मतों में से 154 मत प्राप्त हुए, जो श्रेणी B में सबसे अधिक है, जिसमें 10 प्रमुख समुद्री व्यापार राष्ट्र शामिल हैं।
 - श्रेणी B उन देशों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि है; भारत का पुनः निर्वाचन इसकी बढ़ती समुद्री प्रासंगिकता और प्रभाव को उजागर करता है।
 - भारत के साथ-साथ, श्रेणी B के निर्वाचित सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, जो प्रमुख समुद्री व्यापारिक राष्ट्रों के समूह को दर्शाते हैं।
- ♦ महत्व:
 - यह भारत का लगातार दूसरा द्विवार्षिक सम्मेलन है, जिसमें उसे श्रेणी B में सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए हैं तथा यह अमृत काल समुद्री विज्ञान 2047 के तहत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी समुद्री केंद्र बनने की दिशा में प्रगति को बल देता है।
 - यह अधिदेश सुरक्षित, संरक्षित, कुशल और हरित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है तथा देश को वैश्विक नौवहन नीतियों को आकार देने में एक विश्वसनीय समर्थक के रूप में स्थापित करता है।

एयर मार्शल तेजबीर सिंह महानिदेशक (निरीक्षण एवं सुरक्षा) नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने 1 दिसंबर, 2025 को वायु सेना मुख्यालय में महानिदेशक (निरीक्षण और सुरक्षा) के रूप में कार्यभार संभाला।

मुख्य बिंदु

- ♦ परिचय
 - उनके पास 37 वर्षों का विशिष्ट सैन्य अनुभव है, जिसके दौरान उन्होंने बांग्लादेश में एयर अताचे (Air Attaché), राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में वरिष्ठ निर्देशन स्टाफ तथा वायु सेना संचालन (परिवहन एवं हेलीकॉप्टर) के सहायक वायु सेना प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण कमांड एवं स्टाफ दायित्वों का निर्वहन किया है।
- ♦ शिक्षा:
 - वह यूनाइटेड किंगडम स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ परिचालन विशेषज्ञता:

- 7,000 से अधिक उड़ान घंटों के व्यापक अनुभव के साथ उन्होंने C-130J 'सुपर हरक्यूलिस' विमान की परिचालन भूमिका के अधिष्ठापन में अग्रणी योगदान दिया तथा संयुक्त अभियानों हेतु प्रथम विशेष परिचालन स्क्वाड्रन की स्थापना का नेतृत्व किया।
- उन्होंने उत्तरी क्षेत्र में दो प्रमुख उड़ान अड्डों, एक प्रमुख प्रशिक्षण अड्डे और एक अग्रिम पंक्ति के एयरबेस की कमान सँभाली है तथा हाल ही में मुख्यालय प्रशिक्षण कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण परिवर्तन का नेतृत्व किया है।



❖ सम्मान और उत्तराधिकार:

- वह वायु सेना पदक (2010) तथा अति विशिष्ट सेवा पदक (2018) के सम्मानित प्राप्तकर्ता हैं।
- उन्होंने एयर मार्शल मकरंद भास्कर रानाडे का स्थान लिया, जो 39 वर्षों की सेवा के उपरांत 30 नवंबर, 2025 को सेवानिवृत्त हुए।

सैटेलाइट-लिंकड हेरॉन एमके II (UAVs)

चर्चा में क्यों ?

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, अतिरिक्त सैटेलाइट-लिंकड हेरोन एमके II मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के लिये नए आपातकालीन खरीद आदेश जारी किये हैं।

मुख्य बिंदु

- तीनों सेनाओं में शामिल करना:
 - थलसेना और वायु सेना अपने मौजूदा हेरोन एमके II बेड़े (Fleet) का विस्तार कर रही हैं। जबकि भारतीय नौसेना इस प्लेटफॉर्म को पहली बार अपनाएगी।
 - भारतीय नौसेना समुद्री निगरानी के लिये पुराने इजरायली सर्चर UAVs से अधिक उन्नत हेरोन एमके II प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित होगी।
- संचालन तैनाती: भारतीय सेना पहले ही हेरोन एमके II ड्रोन को उत्तरी क्षेत्र के अग्रिम आधारों पर खुफिया, निगरानी और सैन्य सर्वेक्षण के लिये तैनात कर चुकी है।
- युद्ध मूल्य: हेरोन एमके II जैसे UAVs उच्च-महत्व वाले खतरों, जिसमें उन्नत वायु रक्षा प्रणाली शामिल हैं, का पता लगाने, ट्रैक करने और निष्प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण हैं।
- आपातकालीन सीमाएँ: आपातकालीन खरीद नियमों के तहत, 300 करोड़ रुपये तक की लागत वाली प्रणालियाँ बिना किसी लंबी प्रक्रिया के प्राप्त की जा सकती हैं।
- स्वदेशीकरण को बढ़ावा: इजरायली रक्षा उद्योग भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ सहयोग कर उत्पादन, प्रशिक्षण, रखरखाव तथा प्रणाली एकीकरण को स्थानीयकरण कर रहा है, जो 'मेक इन इंडिया' के अनुरूप है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





हेरॉन एमके II

- ♦ उच्च प्रदर्शन: हेरोन एमके II एक मध्यम-ऊँचाई, दीर्घ-अवधि क्षमता वाला UAV है, जो लगभग 500 किग्रा पेलोड ले जा सकता है और लगातार 24 घंटे से अधिक उड़ान भर सकता है।
- ♦ उन्नत सेंसर: यह सिंथेटिक एपर्चर राडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम तथा सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) सेंसर के माध्यम से सभी मौसम में खुफिया जानकारी प्रदान करता है।
- ♦ दूरस्थ परिचालन: एन्क्रिप्टेड उपग्रह संचार तथा पूर्णतया स्वचालित टेक-ऑफ/लैंडिंग इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं, जो इसे दृष्टि-रेखा से परे मिशनों, लचीली परिचालन योजना तथा विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में प्रभावी तैनाती को सक्षम बनाती हैं।

विवेक चतुर्वेदी CBIC प्रमुख नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 1990 बैच के IRS (सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर) अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- ♦ उन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया, जो 30 नवंबर, 2025 को सेवानिवृत्त हुए।

मुख्य बिंदु

- ♦ उनके पास सीमाशुल्क प्रशासन, खुफिया, सतर्कता, डेटा विश्लेषण तथा जोखिम प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



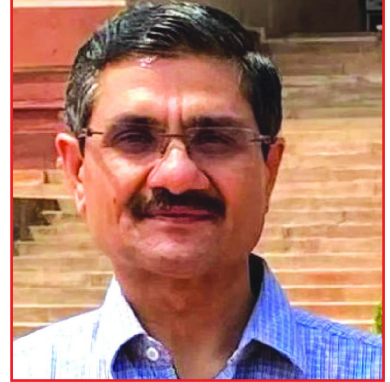
IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- वे वर्तमान में CBIC में सदस्य (Tax Policy & Legal) के रूप में कार्यरत हैं तथा इससे पूर्व विवेक रंजन के स्थान पर बोर्ड में शामिल हुए थे।
- विदेश मंत्रालय में ब्रुसेल्स (2007-2011) में प्रथम सचिव के रूप में उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को अगली पीढ़ी के सीमा शुल्क सुधारों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
- अध्यक्ष के रूप में वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के संघीय बजट की तैयारियों में एक मुख्य भूमिका निभाएंगे, विशेषकर अप्रत्यक्ष करों के लिये, ऐसे समय में जब GST दरों में परिवर्तन तथा राजस्व-लचीलेपन बनाए रखने की आवश्यकता है।
- उनसे सीमा-शुल्क आधुनिकीकरण के अगले चरण का नेतृत्व करने की अपेक्षा है, जिसमें डिजिटलीकरण, त्वरित क्लीयरेंस, सख्त अनुपालन-व्यवस्थाएँ तथा अधिक प्रौद्योगिकी-संचालित GST और सीमा-शुल्क पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।



केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है।
- यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा IGST के अधिरोपण और संग्रहण से संबंधित नीति-निर्माण, तस्करी की रोकथाम एवं CBIC के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, IGST और नारकोटिक्स से संबंधित मामलों के प्रशासन के कार्यों से संबंधित है।
- बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों—कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा केंद्रीय GST आयुक्तालयों तथा सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लेबोरेटरी का प्रशासनिक प्राधिकरण है।

ALIMCO का 53वाँ स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों ?

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) ने अपना 53वाँ स्थापना दिवस एक नए कॉर्पोरेट लोगो का अनावरण करके और दो गतिशीलता समाधानों एक 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) स्कूटर तथा एक क्लिप-ऑन मोटराइज्ड व्हीलचेयर को लॉन्च करके मनाया।

- ALIMCO ने 80 से अधिक स्टार्ट-अप्स के साथ सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहलों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समर्थित और स्मार्ट डिजिटल सहायक प्रौद्योगिकियों के विकास की घोषणा की, ताकि संपूर्ण देश में उच्च-गुणवत्ता वाले, सुलभ सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें।

मुख्य बिंदु

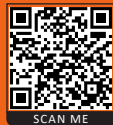
- स्थिति:
 - भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत अनुसूची 'C' मिनरील श्रेणी II केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन कार्यरत है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



♦ **स्वामित्व:**

- यह 100% सरकारी स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

♦ **उद्देश्य:**

- इसका मुख्य उद्देश्य पुनर्वास उपकरणों का निर्माण करके दिव्यांगजनों को लाभान्वित करना तथा देश में कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों की व्यापक उपलब्धता, आपूर्ति तथा वितरण सुनिश्चित करना है।

♦ **गैर-लाभकारी अभिमुखता:**

- बिना किसी लाभ के उद्देश्य से संचालित, इसका प्राथमिक उद्देश्य अधिकतम संख्या में दिव्यांगजनों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है।

♦ **संपर्क का विस्तार:**

- **दिव्यांगजन सहायता (ADIP) योजना** के अंतर्गत कवरेज को व्यापक बनाने हेतु ALIMCO ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों में **प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र (PMDK)** की स्थापना आरंभ की है।

♦ **विशिष्टता:**

- ALIMCO देश का एकमात्र विनिर्माण संगठन है, जो सभी प्रकार की दिव्यांगताओं हेतु एक ही छत के नीचे सहायक उपकरणों की संपूर्ण श्रृंखला का उत्पादन करता है।

संचार साथी ऐप

चर्चा में क्यों ?

दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल निर्माताओं तथा आयातकों को निर्देश दिया है कि **संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन** भारत में बेचे जाने वाले सभी उपकरणों में **प्री-इंस्टॉल** तथा **आसानी से उपलब्ध** होनी चाहिये।

- ♦ यह निर्देश **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In)** को सूचित साइबर-घटनाओं में तीव्र वृद्धि के बाद जारी किया गया है, जो वर्ष 2023 में 15.92 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में 20.41 लाख हो गए हैं, जिनमें 1.23 लाख डिजिटल-अरेस्ट मामले भी शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

- ♦ दूरसंचार विभाग (DOT) ने नागरिकों को पहचान-चोरी, **फर्जी अपने ग्राहक को जानो (KYC)** धोखाधड़ी, डिवाइस चोरी तथा **वित्तीय साइबर-अपराधों** से बचाने के लिये **संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन** लॉन्च किया।
- ♦ गोपनीयता-प्रथम डिज़ाइन (Privacy-First Design): एप्लिकेशन केवल उपयोगकर्ता की सहमति से कार्य करता है, जिसे कभी भी एक्टिव या डिलीट किया जा सकता है तथा **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** और **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** का पालन करता है, जिससे न्यूनतम डेटा-संग्रह तथा शून्य वाणिज्यिक प्रोफाइलिंग सुनिश्चित होती है।
- ♦ राष्ट्रीय दूरसंचार विनियम: यह पहल स्पैम, घोटालों तथा अवांछित वाणिज्यिक संचार की आसान रिपोर्टिंग को सक्षम बनाकर **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)** के नियमों, विशेषकर दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (TC-CCPR) के प्रवर्तन को मजबूत करती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- नागरिक-केंद्रित सेवाएँ: प्रमुख विशेषताओं में धोखाधड़ी कॉल/SMS/व्हाट्सएप संदेशों की रिपोर्टिंग के लिये **चक्षु (Chakshu)**: चोरी हुए उपकरणों के लिये IMEI ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग; मोबाइल कनेक्शन का सत्यापन; मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जाँच; भारतीय (+91) नंबरों के रूप में नकली अंतर्राष्ट्रीय कॉल की रिपोर्टिंग तथा अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता को जानें लुकअप टूल शामिल हैं।
- महत्त्व: **एंड्रॉइड** और **iOS** दोनों पर हिंदी तथा **21 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं** में उपलब्ध यह एप्लिकेशन नागरिक भागीदारी (जन भागीदारी) को सशक्त बनाता है, सार्वजनिक डैशबोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करता है तथा सुरक्षित दूरसंचार उपयोग के लिये राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल विश्वास स्थापित करता है।
- वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI): दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक विकसित किया है, जो मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च अथवा अत्यधिक उच्च धोखाधड़ी-जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जिससे बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) तथा एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सेवा प्रदाताओं को क्षति से बचने में सहायता मिलती है और अब तक 475 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा चुका है।

असम दिवस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दिवस पर असम के लोगों को बधाई दी।

मुख्य बिंदु

- दिवस के बारे में:
 - असम राज्य सरकार ने शिवसागर ज़िले के नाज़िरा में भव्य समारोह के साथ असम दिवस (सुकफा दिवस) मनाया।
 - यह कार्यक्रम सांस्कृतिक मामलों के विभाग और ताई अहोम विकास परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
 - समारोह में पारंपरिक अहोम अनुष्ठान, सांस्कृतिक प्रदर्शन और **अहोम राजवंश** के योगदान को उजागर करने वाली प्रदर्शनियाँ शामिल थीं।
- स्मरणोत्सव:
 - 2 दिसंबर को असम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो वर्ष 1228 में **चाओलुंग सुकफा** के वर्तमान चीन के देहोंग दाई और जिंगपो प्रांत से पटकाई पहाड़ियों को पार करने के बाद असम में आगमन की याद में मनाया जाता है।
- संस्थापक:
 - यह दिवस सुकफा को **अहोम साम्राज्य** के संस्थापक के रूप में सम्मानित करता है, जिनकी 'बोर असोम' विरासत लगभग छह शताब्दियों तक (1826 तक) चली।
 - अहोम शासकों ने असम की पहचान और क्षेत्र की रक्षा की तथा कई **मुगल आक्रमणों** को विफल किया।
- उत्पत्ति:
 - वह माओ-शान उप-जनजाति के सु (टाइगर) कबीले के एक ताई राजकुमार थे, जो मूल रूप से वर्तमान देहोंग दाई और जिंगपो क्षेत्र के मोंग माओ से थे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



♦ शासन:

- उनके प्रशासन ने सुदृढ़ शासन, राजनीतिक स्थिरता और दीर्घकालिक राज्य निर्माण के प्रारंभिक मानक स्थापित किये।
- अहोमों ने पुराने राजनीतिक व्यवस्था भुइयाँ (ज़मींदारों) को दबाकर नया राज्य स्थापित किया।

♦ समाज:

- अहोम समाज कुलों या खेलों (khels) में विभाजित था। एक खेल अक्सर कई गाँवों पर नियंत्रण रखता था।

♦ विरासत:

- सुकफा को असमिया पहचान के निर्माता के रूप में याद किया जाता है, जो एकता से प्रेरित, समावेशी नेतृत्व के लिये जाने जाते हैं और जिन्होंने विभिन्न समुदायों को संगठित करने का प्रयास किया।

नौसेना दिवस 2025

चर्चा में क्यों ?

भारतीय नौसेना 3-4 दिसंबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम के शंगुमुघम समुद्र तट पर व्यापक स्तर पर परिचालन प्रदर्शन के साथ **नौसेना दिवस** मना रही है।

- जिसमें भारत के **राष्ट्रपति** और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं तथा इस कार्यक्रम की मेज़बानी नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

परिचालन प्रदर्शन 2025

♦ संपर्क एवं पहुँच (Outreach):

- यह समारोह नौसेना दिवस के कार्यक्रमों को प्रमुख नौसैनिक अड्डों से परे आयोजित करने की भारतीय नौसेना की पहल का हिस्सा है। इससे पहले पुरी और सिंधुदुर्ग में भी कार्यक्रम आयोजित किये गए थे।

♦ प्रदर्शन (Showcase):

- परिचालन प्रदर्शन में **युद्धपोतों**, नौसैनिक विमानों और **पनडुब्बियों** द्वारा समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है।

♦ तत्परता:

- यह प्रदर्शन भारतीय नौसेना के “युद्ध के लिये तैयार, एकजुट और आत्मनिर्भर” होने के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है।

♦ आत्मनिर्भरता:

- यह स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक प्लेटफार्मों पर केंद्रित है, जो **आत्मनिर्भर भारत** और **मेक इन इंडिया पहल** के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नौसेना दिवस

❖ स्मरणोत्सव:

- वर्ष 1971 के **भारत-पाकिस्तान युद्ध** में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारत की निर्णायक नौसैनिक जीत के सम्मान में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
- ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान, भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने कराची में पाकिस्तानी जहाजों, तेल सुविधाओं और **तटीय सुरक्षा** पर सफलतापूर्वक हमला किया।
- भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण युद्ध सामग्री ले जा रहे कई पाकिस्तानी जहाजों को नष्ट कर दिया, जिससे **पाकिस्तान की परिचालन क्षमता** कमजोर हो गई।

❖ वायुशक्ति:

- INS विक्रान्त** के लड़ाकू विमानों ने चटगाँव और खुलना में दुश्मन के बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों पर हमला किया। कराची पर मिसाइल हमलों के साथ-साथ इन हमलों ने **पूर्वी पाकिस्तान** में पाकिस्तानी सेना को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऑपरेशन सागर बंधु

चर्चा में क्यों ?

भारतीय नौसेना ने **चक्रवाती तूफान दित्वा** से प्रभावित श्रीलंका में **ऑपरेशन सागर बंधु** के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान आरंभ किया।

मुख्य बिंदु

- तैनाती (Deployment): भारत ने **INS विक्रान्त**, **INS उदयगिरि** और भारतीय वायु सेना के **C-130J** विमान के माध्यम से तंबू, कंबल, खाद्य सामग्री, स्वच्छता किट एवं टारपोलिन भेजे, ताकि श्रीलंका में सहायता प्रदान की जा सके।
- पुनःआवंटन (Reassignment): **INS विक्रान्त** और **INS उदयगिरि**, जो 75वीं वर्षगांठ अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा (International Fleet Review) के लिये कोलंबो में पहले से मौजूद थे, उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुँचाने के लिये पुनः आवंटित किया गया।
- राहत एवं बचाव (Rescue): जहाजों पर आधारित हेलीकॉप्टरों ने **हवाई सर्वेक्षण** किया और खोज एवं बचाव (Search and Rescue) अभियान में मदद की, जिसमें श्रीलंकाई नागरिकों को बचाया गया।
- सुदृढ़ीकरण (Reinforcement): **INS सुकन्या** को 1 दिसंबर, 2025 को त्रिनकोमाली में अतिरिक्त आवश्यक सामग्री के साथ राहत प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिये तैनात किया गया।
- प्रतिबद्धता (Commitment): यह मिशन भारत के श्रीलंका के प्रति सतत मानवीय समर्थन को दर्शाता है, जो **नेबरहुड फर्स्ट' नीति** और विज्ञान महासागर के अनुरूप है, जैसा कि पहले **चक्रवात रोआनू** (2016) एवं **MV एक्सप्रेस पर्ल आपदा** (2021) के दौरान सहायता में देखा गया था।
- भारत के पूर्व अभियान:
 - नेपाल में **ऑपरेशन मैत्री**
 - इंडोनेशिया में ऑपरेशन समुद्र मैत्री
 - तुर्किये और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026UPSC
क्लासरूम
कोर्सेसIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

♦ भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास:

- बिस्मटेक देशों के साथ पैनेक्स-21
- आसियान देशों के साथ समन्वय-22

नोट:

- ♦ चक्रवात दित्वा एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो **बंगाल की खाड़ी** के दक्षिण-पश्चिमी में तीव्र गति से विकसित हुआ।
- दित्वा नाम यमन द्वारा दिया गया था, जो उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवातों के लिये क्षेत्रीय नामकरण प्रणाली का अनुसरण करता है।

भारत-मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास **एकुवेरिन** का 14वाँ संस्करण 2 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2025 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

- ♦ भागीदारी: गढ़वाल राइफल्स बटालियन की 45 सदस्यीय **भारतीय सेना** की टुकड़ी, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की 45 सदस्यीय टुकड़ी के साथ प्रशिक्षण ले रही है।
- ♦ अर्थ: **एकुवेरिन**, जो धिवेही शब्द “मित्र” से लिया गया है, भारत और मालदीव के बीच विश्वास तथा सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है।
- ♦ परंपरा: वर्ष 2009 से दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित यह अभ्यास **भारत की नेबरहुड फर्स्ट' नीति** का एक प्रमुख घटक है।
- ♦ प्रशिक्षण: सैनिक जंगल, अर्द्ध-शहरी और तटीय क्षेत्रों में संयुक्त उग्रवाद-रोधी तथा आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ♦ समन्वय: इस अभ्यास में संयुक्त मिशन योजना, सामरिक अभ्यास और समन्वित परिचालन प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान शामिल है।
 - इसका उद्देश्य दोनों बलों के बीच अंतर-संचालन क्षमता में सुधार और संचालनात्मक सहकार्य (operational synergy) बढ़ाना है।
- ♦ स्थिरता: यह अभ्यास **हिंद महासागर क्षेत्र** में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति भारत तथा मालदीव के बढ़ते रक्षा सहयोग एवं आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ज्ञानेश कुमार ने IDEA परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की

चर्चा में क्यों ?

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने **स्टॉकहोम, स्वीडन** में वर्ष 2026 के लिये **अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान (International IDEA)** की सदस्य-राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण की।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

❖ पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1995 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय IDEA के वर्तमान में 35 सदस्य देश हैं; संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं।
- वर्ष 2003 से इसे **संयुक्त राष्ट्र महासभा** में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

❖ साझेदारी:

- भारत के नेतृत्व में मॉरीशस और मैक्सिको वर्ष 2026 के लिये उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे।

❖ वैश्विक मान्यता:

- यह अध्यक्षता भारत के लिये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है, जो **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)** को विश्व के सबसे विश्वसनीय, पारदर्शी और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन निकायों में स्थापित करती है।
- भारत, एक **संस्थापक सदस्य** होने के नाते, IDEA के शासन और लोकतांत्रिक पहलों में निरंतर योगदान देता रहा है।

❖ विज्ञान:

- CEC ज्ञानेश कुमार ने आश्वासन दिया कि भारत की अध्यक्षता निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यान्वयन-उन्मुख होगी।
- यह “समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और स्थायी विश्व के लिये लोकतंत्र” थीम से निर्देशित रहेगी तथा दो मुख्य स्तंभों पर केंद्रित होगी:
 - भविष्य के लिये लोकतंत्र की पुनर्कल्पना,
 - स्थायी लोकतंत्र हेतु स्वतंत्र एवं पेशेवर चुनाव प्रबंधन निकायों का सुदृढीकरण।

भारत की प्रथम पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के प्रथम पूर्ण-इलेक्ट्रिक ग्रीन टग को वर्चुअली प्रस्थान-संकेत दिया, जो **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP)** के तहत सतत तथा ऊर्जा-कुशल समुद्री परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि है।

टग (या टगबोट) एक शक्तिशाली तथा अत्यधिक नियंत्रित रूप से संचालित होने वाला पोत है, जिसका उपयोग बड़े जहाजों को बंदरगाह क्षेत्रों में मार्गदर्शन, टोइंग, बर्थिंग, एस्कोर्टिंग तथा आपात प्रतिक्रिया जैसे परिचालनों में किया जाता है, विशेषकर उन सीमित जलक्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक परिशुद्धता की आवश्यकता होती है।

मुख्य बिंदु

❖ उद्देश्य तथा डिज़ाइन:

- दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA), **कांडला** के लिये निर्मित यह टगबोट भारत के समुद्री डी-कार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु विकसित किया जा रहा है।
- यह शांत संचालन, **शून्य कार्बन उत्सर्जन**, अनुकूलित ऊर्जा दक्षता तथा 60-टन बोल्ड-पुल क्षमता सुनिश्चित करेगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



♦ GTTP रोडमैप:

- ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50 ग्रीन टग शामिल करना है। चरण-I (2024-2027) में 16 टग निर्धारित हैं।
- DPA, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी तथा VO चिंदबरनार पोर्ट अथॉरिटी में दो-दो टग स्थापित किये जाएंगे, जिनमें DPA निर्माण प्रारंभ करने वाला पहला बंदरगाह होगा।

♦ भविष्य का एकीकरण:

- तैनाती के उपरांत यह टग शून्य उत्सर्जन के साथ बंदरगाह संचालन, अनुरक्षण तथा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में सहयोग करेगा। यह भविष्य के GTTP चरणों के लिये महत्वपूर्ण परिचालन डेटा भी उत्पन्न करेगा।
- यह पहल मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030, अमृतकाल प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय डी-कार्बोनाइजेशन ढाँचों के अनुरूप है।

♦ रणनीतिक प्रभाव:

- DPA की यह पहल भारत के स्वच्छ-ऊर्जा बंदरगाहों की ओर संक्रमण को रेखांकित करती है, अत्रेय शिपयार्ड के माध्यम से मेक इन इंडिया जहाज-निर्माण को सुदृढ़ बनाती है और देश को हरित समुद्री नवाचार के एक उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

खुदीराम बोस जयंती

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें वीरता, साहस और बलिदान का शाश्वत प्रतीक बताया।

मुख्य बिंदु

♦ जन्म और प्रारंभिक जीवन:

- खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर, 1889 को हबीबपुर गाँव, मिदनापुर ज़िले, पश्चिम बंगाल में हुआ था।
- वे अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे, माता-पिता के निधन के कारण उन्हें बचपन में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

♦ प्रारंभिक प्रभाव:

- अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के सार्वजनिक भाषणों से प्रेरित होकर, वे 1900 के दशक के प्रारंभ में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए।

♦ विभाजन आंदोलन में भूमिका:

- वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान, वे एक सक्रिय स्वयंसेवक बन गए और मात्र 15 वर्ष की आयु में ब्रिटिश-विरोधी पर्चे बाँटने के कारण उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया।

♦ अनुशीलन समिति में शामिल होना:

- वर्ष 1908 में, खुदीराम अरबिंदो और बारींद्र घोष के नेतृत्व वाले क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए, जहाँ उन्होंने बम बनाना सीखा तथा ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया।
- क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस एच. किंग्सफोर्ड को, जो राष्ट्रवादियों के साथ क्रूर व्यवहार के लिये जाने जाते थे, अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाया और खुदीराम तथा प्रफुल्ल चाकी को उनकी हत्या करने के लिये भेजा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ बम हमले का प्रयास:

- 30 अप्रैल, 1908 को खुदीराम ने क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन इससे बैरिस्टर की पत्नी और बेटी श्रीमती तथा मिस कैनेडी की दुखद मौत हो गई, जबकि किंग्सफोर्ड बच निकला।

❖ गिरफ्तारी और परिणाम:

- प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से पूर्व ही आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम को 25 किमी. पैदल चलने के बाद वैनी स्टेशन पर पकड़ लिया; उनकी गिरफ्तारी के समय स्थानीय जनता ने उनकी निर्भीकता और राष्ट्रनिष्ठा की सराहना की।

❖ फाँसी और शहादत

- मुकदमे के बाद, खुदीराम बोस को 11 अगस्त, 1908 को 18 वर्ष की आयु में फाँसी दे दी गई, जो भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थे।
- समाचार-पत्रों ने उनकी बहादुरी को उजागर किया गया, उनकी अंतिम यात्रा के दौरान भीड़ ने फूल बरसाए और कवि पीतांबर दास ने प्रसिद्ध बंगाली गीत “एक बार बिदाये दे मा” में उन्हें अमर कर दिया, जिससे बंगाल की लोककथाओं में उनकी विरासत संरक्षित हो गई।

अंटार्कटिका दिवस

चर्चा में क्यों ?

भारत ने 1 दिसंबर, 2025 को **अंटार्कटिका दिवस** मनाया और साथ ही **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR)**, गोवा की 25वीं वर्षगांठ का उत्सव भी मनाया, जिसने ध्रुवीय तथा महासागरीय अन्वेषण में देश के अग्रणी संस्थान के रूप में इसकी भूमिका की पुष्टि की।

मुख्य बिंदु

अंटार्कटिका दिवस

- संधि पर हस्ताक्षर (1959): अंटार्कटिका संधि पर 1 दिसंबर, 1959 को 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे, जिसके तहत पृथ्वी के लगभग 10% क्षेत्र का उपयोग पूरी मानवता के लाभ के लिये विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये किया जाना था।
- ऐतिहासिक पहल: यह संधि पहला परमाणु-हथियार नियंत्रण समझौता बन गई तथा पहली ऐसी संस्थान बन गई है, जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मानव गतिविधियों का नियंत्रण करती है।
- अंटार्कटिक संधि शिखर सम्मेलन (2009): वर्ष 2009 में 50वीं वर्षगांठ शिखर सम्मेलन में अंटार्कटिक संधि के तहत शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पाँच दशकों का उत्सव मनाया गया।
- अंटार्कटिका दिवस का निर्माण (2010): 50 वर्ष के समारोहों से प्रेरित होकर, फाउंडेशन फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल स्पेसेस (आवर स्पेसेस) ने वर्ष 2010 में अंटार्कटिका दिवस की शुरुआत की।
- उद्देश्य: अंटार्कटिका दिवस का उद्देश्य संधि के बारे में वैश्विक जागरूकता प्रचारित करना तथा इसे मानव सभ्यता में शांति और सहयोग के एक उपलब्धि के रूप में मनाना है।
- भारत की भूमिका: भारत वर्ष 1983 से एक परामर्शदात्री पक्ष रहा है, जिससे उसे मतदान का अधिकार मिला है और अनुसंधान केंद्रों को संचालित करने तथा अंटार्कटिका के वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय शासन में योगदान करने की क्षमता मिली है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र (NCPOR)

♦ स्थापना:

- इसकी स्थापना वर्ष 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत की गई थी। यह भारत के अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय और अनुसंधान स्टेशनों- मैत्री (1989) तथा भारती (2011) के रखरखाव के लिये नोडल एजेंसी है।

♦ भूमिका:

- गोवा में स्थित यह केंद्र बहु-विषयक ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर अनुसंधान का नेतृत्व करता है तथा इसमें पीएच.डी. अध्ययन हेतु मान्यता प्राप्त अनुसंधान सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह भारत के डीप ओशन मिशन में भी मुख्य भूमिका निभाता है, जिससे ध्रुवीय विज्ञान को रणनीतिक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जाता है।

♦ अनुसंधान केंद्र: NCPOR ने भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है: दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती (अंटार्कटिका) और हिमाद्री (आर्कटिक), साथ ही हिमालयी अनुसंधान केंद्र हिमांश भी संचालित करता है।

♦ भविष्य की पहल: वित्त मंत्रालय ने मैत्री-II, एक नया पूर्वी अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र, जो NCPOR द्वारा संचालित होगा, को अनुमोदित किया है।

BSF स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रधानमंत्री ने BSF के सुरक्षा-कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने तथा मानवीय कार्यों में उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।

मुख्य बिंदु

- ♦ **स्थापना:** BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिये की गई थी।
 - यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की 6,000 किमी. से अधिक भूमि सीमा की सुरक्षा करता है।
- ♦ **मानवीय योगदान:** BSF अपनी सुरक्षा ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ मानवीय गतिविधियों के लिये भी जाना जाता है, जिनमें शामिल हैं:
 - आपदा राहत अभियान
 - सीमावर्ती गाँवों में सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम
 - चिकित्सा शिविर और शैक्षणिक सहायता
- ♦ **परिचालन उत्कृष्टता:** BSF आतंकवाद विरोधी, तस्करी विरोधी और घुसपैठ विरोधी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाता है।
 - इसके कर्मिकों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में असाधारण बहादुरी दिखाई है:
 - अंतर्राष्ट्रीय सीमा गश्त
 - आतंकवाद विरोधी कार्रवाई
 - नागरिक अधिकारियों के साथ शांति स्थापना और सहयोग

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारत के सात सुरक्षा बल शामिल हैं।

असम राइफल (AR)

- स्थापना: वर्ष 1835, मिलिशिया के रूप में जिसे 'कछार लेवी' के नाम से जाना जाता था।
- पूर्ववर्ती उद्देश्य: ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा करना।
- वर्तमान उद्देश्य:
 - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना।
 - भारत-चीन और भारत-म्यांमार सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- महत्वपूर्ण भूमिका:
 - भारत-चीन युद्ध, 1962
 - श्रीलंका के लिये भारतीय शांति रक्षा सेना (IPKF) (1987) के रूप में।

आदिवासी इलाकों से लंबे जुड़ाव के कारण असम राइफल को 'उत्तर पूर्व का मित्र' भी कहा जाता है।

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- स्थापना: वर्ष 1965
- उद्देश्य:
 - पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाओं को सुरक्षित करना।
 - साथ ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ की समस्याओं को रोकना।
 - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में उग्रवाद का मुकाबला करना।
 - ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाना।
- विंग: एयर विंग, समुद्री विंग, आर्टिलरी रेजीमेंट और कमाण्डो यूनिट्स।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत का पहला लाइन ऑफ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)

- स्वतंत्रता-पूर्व स्थापना: वर्ष 1939 (क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस)।
- स्वतंत्रता के पश्चात: वर्ष 1949 - CRPF अधिनियम के तहत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में नामित किया गया।
- उद्देश्य: भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, काउंटर मिलिटेंसी/उग्रवाद संचालन, आदि।

CRPF आंतरिक सुरक्षा के लिये प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- स्थापना: वर्ष 1962।
- उद्देश्य:
 - काराकोरम दर्रे (लद्दाख) से जंचेप ला (अरुणाचल प्रदेश) तक सीमा पर तैनात (भारत-चीन सीमा का 3488 कि.मी. कवर करती है)।
 - भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 9000 फीट से 18700 फीट की ऊँचाई पर स्थित सीमा चौकियों की निगरानी।

ITBP एक विशेष पर्वतीय सैन्य बल है; जिसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता कहा जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- स्थापना: वर्ष 1984 (1986 में अस्तित्व में आया), ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात्।
- उद्देश्य: आतंकवाद-रोधी इकाई/संघीय आक्रामक बल।
- टास्क ओरिएंटेड फोर्स- दो पूरक शाखाएँ:
 - स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG)।
 - स्पेशल रेंजर ग्रुप (SRG)।

सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- स्थापना: वर्ष 1963
- उद्देश्य:
 - भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करना।
 - सीमा सुरक्षा बढ़ाना, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना, अनधिकृत प्रवेश/निकास को रोकना, तस्करी रोकना, आदि।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- स्थापना: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत।
- उद्देश्य: महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

CISF एक विशेष फायर विंग वाली एकमात्र CAPF यूनिट है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नागालैंड राज्य दिवस

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर बधाई दी तथा राज्य की समृद्ध संस्कृति और राष्ट्र के प्रति योगदान की प्रशंसा की।



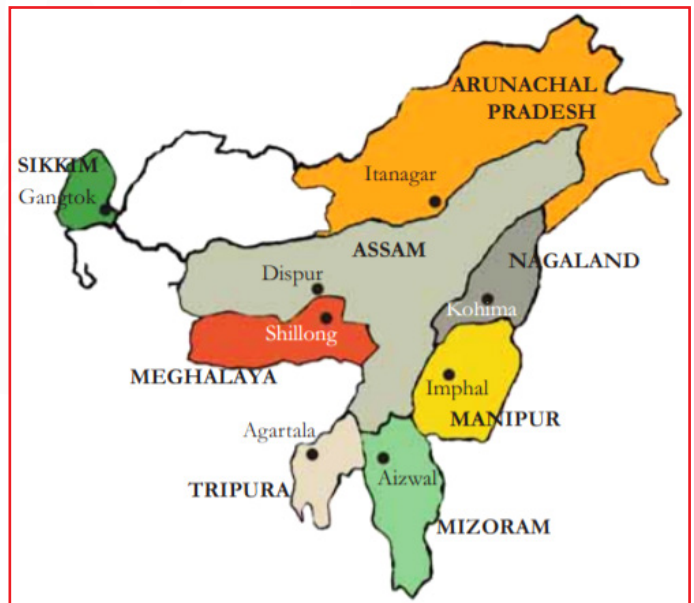
मुख्य बिंदु

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- नागालैंड 1 दिसंबर, 1963 को भारत का 16वाँ राज्य बना, जिससे नागा लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई।
- क्षेत्र में शांति, स्वायत्तता और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरंतर वार्ता के बाद इस राज्य का गठन किया गया।

सांस्कृतिक पहचान:

- नागालैंड 16 प्रमुख विशिष्ट जनजातियों का आश्रय है, जैसे- अंगामी, एओ, कोन्याक और सुमी, जो अपनी विशिष्ट बोलियों, रंगीन योद्धा वेशभूषा और लोकतांत्रिक ग्राम शासन के लिये प्रसिद्ध हैं।
- दिसंबर में मनाया जाने वाला हॉर्नबिल महोत्सव 16 नागा जनजातियों की विरासत को प्रदर्शित करता है और संपूर्ण विश्व से पर्यटकों को आकर्षित करता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर) के अवसर पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किये और समावेशी विकास में उनकी भूमिका को रेखांकित किया।

मुख्य बिंदु

♦ दिवस के बारे में:

- वर्ष 2025 का विषय: “Fostering disability-inclusive societies for advancing social progress” अर्थात सामाजिक प्रगति के लिये दिव्यांगजन-समावेशी समाज का संवर्द्धन।
- यह विषय भारत के कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव के अनुरूप है।
- वर्ष 2015 से अपनाया गया शब्द “दिव्यांगजन” विकलांग व्यक्तियों के प्रति सम्मान और गरिमा का प्रतीक है।

♦ दिव्यांगजनों से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहलें:

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: मान्यता प्राप्त दिव्यांगता श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया।
- सुगम्य भारत अभियान: यह एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख मिशन है, जिसका लक्ष्य तीन प्रमुख स्तंभों- निर्मित पर्यावरण, परिवहन और ICT परिस्थितिकी तंत्रों पर है, ताकि सार्वभौमिक रूप से बाधा रहित अवसररचना का निर्माण किया जा सके।
- विशिष्ट विकलांगता पहचान-पत्र (UDID) परियोजना: प्रत्येक दिव्यांगजन को एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डाटाबेस के माध्यम से वैश्विक पहचान-पत्र प्रदान करना, जिससे सभी राज्यों में कल्याणकारी लाभों का निर्बाध वितरण सुनिश्चित हो।
- दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना: राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) के माध्यम से स्वरोजगार उपक्रमों, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये रियायती ऋण प्रदान।
- PM-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही): डिजिटल पोर्टल जो मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण एवं संभावित नियोक्ताओं तथा जॉब एग्रीगेटर्स से प्रत्यक्ष संपर्क प्रदान करता है।
- SIPDA (दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना): राज्य सरकारों और स्वायत्त निकायों को बाधा-मुक्त वातावरण तथा पुनर्वास केंद्रों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान।

EARTH समिट 2025

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में EARTH समिट 2025 का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

♦ सम्मेलन के बारे में:

- EARTH समिट (तीन-भागीय शृंखला) का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ग्रामीण विकास से संबद्ध चार मंत्रालयों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का समाधान करना तथा अगले वर्ष दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतिम शिखर सम्मेलन तक एक राष्ट्रीय नीति ढाँचा तैयार करना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





- यह ग्रामीण नवाचार, सहकारी-संचालित विकास और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिये एक सहयोगी ढाँचा बनाने हेतु 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों, 1,200 कॉर्पोरेट्स, 500 विशेषज्ञों, 300 स्टार्टअप्स तथा 250 प्रदर्शकों को एक मंच पर एकत्र करता है।

♦ आयोजक:

- यह शिखर सम्मेलन **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** तथा इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

♦ डिजिटल शुभारंभ:

- कार्यक्रम के दौरान, गृह मंत्री ने 'सहकार सारथी' के अंतर्गत 13 से अधिक नई सहकारी डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया, जिनमें **Digi-KCC**, सहकारी शासन सूचकांक, **ePACS**, अनाज भंडारण अनुप्रयोग, शिक्षा सारथी तथा ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों को एकीकृत करने के लिये प्रौद्योगिकी मंच शामिल हैं।

♦ प्रौद्योगिकी एकीकरण:

- नाबार्ड का 'सहकार सारथी' मंच समस्त सहकारी बैंकों को एक तकनीकी छत्र के अंतर्गत लाएगा, जो वैश्विक ऋण प्रणालियों के समकक्ष आधुनिक बैंकिंग उपकरण, वास्तविक समय ट्रेकिंग, KYC, दस्तावेजीकरण तथा **e-KCC** सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।

♦ मॉडल विस्तार:

- गुजरात के 'सहकारों के मध्य सहकार' मॉडल के अंतर्गत सहकारी संस्थाएँ स्वयं सहकारी तंत्र के भीतर बैंकिंग कार्य करती हैं, जिससे कम-लागत वाली जमा राशि में हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस मॉडल का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जाएगा।

♦ जैविक और प्राकृतिक खेती:

- भारत में वर्तमान में 49 लाख प्राकृतिक किसान सक्रिय हैं तथा 40 से अधिक जैविक उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अमूल तथा भारत ऑर्गेनिक्स के सहयोग से एक राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला नेटवर्क का विकास किया जा रहा है, जो निर्यात को प्रोत्साहन देगा। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 20% तथा वर्ष 2035 तक 40% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी अर्जित करना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



हस्तशिल्प पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह समारोह के भाग के रूप में 9 दिसंबर, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 2024 के लिये प्रतिष्ठित हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेगा।

मुख्य बिंदु

- वर्ष 1965 में स्थापित राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार उन असाधारण शिल्पकारों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कलात्मक उत्कृष्टता के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है।
- गणमान्य व्यक्ति: इस समारोह की अध्यक्षता भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी तथा इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे तथा पबित्रा मार्गेरिटा मुख्य अतिथि होंगे।
- शिल्प गुरु पुरस्कार: वर्ष 2002 में शुरू किये गए शिल्प गुरु पुरस्कार हस्तशिल्प क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान हैं, जो अद्वितीय कौशल और नवाचार को सम्मानित करते हैं।
- राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह: प्रतिवर्ष 8 से 14 दिसंबर तक मनाया जाने वाला यह सप्ताह प्रदर्शनी, कार्यशालाएँ, प्रदर्शन, वार्ताएँ, संपर्क और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि भारत के शिल्पकारों तथा उनकी शिल्प परंपराओं का उत्सव मनाया जा सके।
- क्षेत्रीय महत्त्व: हस्तशिल्प क्षेत्र सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करता है, ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी भारत में लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है तथा राष्ट्रीय निर्यात आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डॉ. अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्य बिंदु

दिवस के बारे में:

- महापरिनिर्वाण दिवस हर वर्ष 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- यह दिवस उनके सामाजिक सुधार, न्याय और समानता पर पड़े परिवर्तनकारी प्रभाव को सम्मानित करता है।
- “महापरिनिर्वाण” शब्द बौद्ध दर्शन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा यह बौद्ध कैलेंडर में सबसे पवित्र दिवस माना जाता है।

प्रमुख योगदान:

- सशक्तीकरण: शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने और बहिष्कृत समुदायों को सशक्त बनाने के लिये बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923) की स्थापना की।
- वकालत: उत्पीड़ितों को मंच प्रदान करने और सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने के लिये मूकनायक (मौन लोगों का नेता) समाचार-पत्र की स्थापना की।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **समानता:** सार्वजनिक जल संसाधनों तक समान पहुँच की वकालत करते हुए **महाड़ सत्याग्रह (1927)** सहित ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया।
- ❖ **मुक्ति:** वर्ष 1930 में पूजा स्थलों में जाति-आधारित प्रतिबंधों को तोड़ने के लिये **कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (नासिक सत्याग्रह)** का नेतृत्व किया, जो अस्पृश्यता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई का प्रतीक था।
- ❖ **प्रतिनिधित्व:** **पूना समझौते** पर बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने दलितों के लिये पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर **आरक्षित सीटें** स्थापित कीं, जिससे उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- ❖ **संविधान:** वर्ष 1947 में नियुक्त **प्रारूप समिति** के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. अंबेडकर ने विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान को तैयार करने की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया की देख-रेख की।
- ❖ **अर्थशास्त्र:** डॉ. अंबेडकर के **डॉक्टरल शोध** ने भारत में **वित्त आयोग** की स्थापना और वर्ष 1934 के **RBI अधिनियम** के नीतिगत ढाँचे को प्रभावित किया।

पुरस्कार और सम्मान:

- ❖ **भारत रत्न पुरस्कार:** डॉ. अंबेडकर को वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, **भारत रत्न** से सम्मानित किया गया।
- ❖ **अंबेडकर सर्किट:** अंबेडकर के जीवन से जुड़े पाँच स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया गया (**पंचतीर्थ विकास**):
 - ❶ महु में जन्मस्थान
 - ❷ लंदन में स्मारक (**शिक्षा भूमि**)
 - ❸ नागपुर में दीक्षा भूमि
 - ❹ मुंबई में चैत्य भूमि
 - ❺ दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि
- ❖ **संविधान दिवस:** संविधान वास्तुकार के रूप में **भूमिका** को सम्मानित करने हेतु वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मानव अधिकार दिवस

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 दिसंबर, 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** के मानवाधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी।

मुख्य बिंदु

- ❖ **दिवस के बारे में:**
 - ❶ **मानवाधिकार दिवस**, जो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, न्याय शांति तथा समानता की आधारशिला के रूप में **मानवाधिकारों** के महत्त्व को रेखांकित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- ⑤ मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- ⑤ मामलों का स्वतः संज्ञान
- ⑤ मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशांसा करना
- ⑤ मानवाधिकार जागरूकता फैलाना
- ⑤ मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- ⑤ व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- ⑤ यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- ⑤ मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- ⑤ 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- ⑤ **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- ⑤ **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- ⑤ **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक

गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- NHRC को वर्ष 1999 से 'A' श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- 'A' श्रेणी की स्थिति: वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- 'A' स्थिति का निलंबन: वर्ष 2023 और वर्ष 2024

कार्यकाल

- ⑤ 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- ⑤ राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- ⑤ **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर



Drishti IAS

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ ऐतिहासिक महत्व:

- मानवाधिकार दिवस की स्थापना वर्ष 1950 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के उपलक्ष्य में की गई थी, जिसे 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत किया गया था और जिसमें सभी व्यक्तियों के लिये मौलिक मानवाधिकारों की रूपरेखा निर्धारित की गई थी।
- वर्ष 2006 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अपने 47 सदस्य देशों (भारत सहित) के माध्यम से वैश्विक मानवाधिकार संरक्षण को सुदृढ़ करती है तथा उल्लंघनों और आपात परिस्थितियों से निपटने हेतु कार्य करती है।
- परिषद का सचिवालय मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) है, जो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

❖ समर्थन और कार्रवाई:

- यह दिवस घृणास्पद भाषण, भ्रांत सूचना तथा मानवाधिकारों के हनन का सामना करने के लिये सामूहिक प्रयासों का आह्वान करता है और समानता सहित निगरानीहीन भेदभाव-रहित व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है।

❖ मानवाधिकार और भारत:

- भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों (भाग III) तथा राज्य-नीति के निदेशक तत्वों (भाग IV) के माध्यम से मानवाधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- प्रस्तावना का न्याय स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व के प्रति संकल्प, UDHR की भावना का प्रतिरूप प्रस्तुत करता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी, देश में मानवाधिकारों के अनुपालन की निगरानी करता है।

❖ थीम:

- NHRC “एंग्योरिंग एवरीडे एसेंशियल्स: पब्लिक सर्विसेज़ एंड डिग्नैटी फॉर ऑल” शीर्षक से एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस की थीम “एवरीडे एसेंशियल्स” के अनुरूप है।

❖ वार्ता:

- दो विषयगत सत्र “बेसिक अमेनिटीज़ टू ऑल: ए ह्यूमन राइट्स एप्रोच” तथा “एंग्योरिंग पब्लिक सर्विसेज़ एंड डिग्नैटी फॉर ऑल” में वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा सेवा-प्रदायन में विद्यमान अंतरालों तथा समाधान पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

बंगलूरु में UNSW कैंपस

चर्चा में क्यों ?

न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर) बंगलूरु में अपना नया कैंपस स्थापित करने जा रहा है, जिसके साथ वह भारत में संचालन हेतु स्वीकृत 19 विदेशी संस्थानों में सम्मिलित 7वाँ ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय बन जाएगा।

- यह संस्थान व्यापार, मीडिया, कंप्यूटर तथा डेटा विज्ञान सहित साइबर सुरक्षा में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा तथा UGC से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आगामी शैक्षणिक वर्ष में कक्षाएँ प्रारंभ होने की संभावना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





मुख्य बिंदु

◆ कैंपस के बारे में:

- तीसरी ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद (AIESC) बैठक में संस्थानों और सरकारों के बीच व्यापक **समझौता ज्ञापन** तथा **आशय पत्रों** पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे **भारत-ऑस्ट्रेलिया शिक्षा सहयोग** में बढ़ते विश्वास और दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धता पर बल मिला।

◆ अनुसंधान:

- संयुक्त **वैज्ञानिक नवाचार** को आगे बढ़ाने के लिये 9.84 करोड़ रुपये के वित्त पोषण द्वारा समर्थित, **AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी, जैव विविधता**, मेडटेक, स्थिरता, स्मार्ट गतिशीलता और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में **SPARC योजना** के तहत दस नई द्विपक्षीय अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू की गईं।

◆ विद्यालय:

- पहली बार, AIESC बैठक ने विद्यालय स्तर पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें **CBSE** के प्रारंभिक बाल्यकाल पाठ्यक्रम को ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाना और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती डायस्पोरा सेवा के लिये अधिक **CBSE-संबद्ध स्कूलों** की स्थापना का अन्वेषण शामिल था।

◆ नवाचार:

- नई अंतर-संस्थागत पहलों में जेम्स कुक विश्वविद्यालय के साथ ओडिशा में एक समुद्री पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र और खनन स्वचालन, रसद तथा स्थिरता पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, IIM मुंबई एवं IIT धनबाद के बीच सहयोग शामिल है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ अनुकूलन:

- डीकैन विश्वविद्यालय और IIT रुड़की आपदा अनुकूलन में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे, जिससे जलवायु प्रतिक्रिया, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण तथा आपातकालीन तैयारी में भारत-ऑस्ट्रेलियाई शैक्षणिक सहयोग को विस्तारित करेगा।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्र ने 7 दिसंबर, 2025 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया तथा रक्षा मंत्री ने वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिये सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदार योगदान देने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु

❖ परिचय:

- सशस्त्र सेना झंडा दिवस (AFFD) प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जो वर्ष 1949 से भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों, विशेषकर पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है।
- यह दिवस न केवल शहीद सैनिकों के बलिदान को, बल्कि उनके परिवारों, विशेषकर युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों और शहीद सैनिकों की पत्नियों (वीर नारियों) के योगदान को भी मान्यता देता है।

❖ ध्वज दिवस कोष (AFFDF):

- इस कोष की स्थापना मूलतः रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1949 में की गई थी। वर्ष 1993 में इसे युद्ध पीड़ितों और पूर्व सैनिकों के विभिन्न कल्याण कोषों को मिलाकर एकीकृत कोष में समेकित किया गया।
- केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) इसके प्रशासन के लिये उत्तरदायी है।
- KSB पूरे भारत में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिये कल्याण तथा पुनर्वास योजनाएँ निर्मित एवं क्रियान्वित करता है।

❖ डिजिटल समाधान:

- व्हाट्सएप-आधारित चैटबॉट, 'SAMBANDH', पूर्व सैनिकों को आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उनका समाधान करने में मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म ने एक वर्ष से भी कम समय में 1,700 से अधिक मामलों का समाधान किया है।

❖ महिलाओं के लिये कौशल विकास:

- महिला सशक्तीकरण पहल का उद्देश्य शहीद सैनिकों की विधवाओं सहित महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है।

❖ प्रोजेक्ट नमन (Project NAMAN):

- इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के लिये पेंशन सेवाओं को सरल बनाना तथा जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने और पेंशन वितरण जैसी सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



बंगलूरु में नया रक्षा MRO हब

चर्चा में क्यों ?

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन ने बंगलूरु में **C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान** के लिये एक नई **रक्षा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO)** सुविधा का निर्माण शुरू किया, जिसे वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



मुख्य बिंदु

- ♦ **विस्तार:**
 - यह सुविधा C-130J, KC-130J और C-130 B-H सहित विभिन्न विमान प्रकारों को समर्थन प्रदान करेगी तथा लॉकहीड मार्टिन के प्रमाणित सेवा केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनेगी।
- ♦ **स्थान:**
 - केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट भट्टरामरेनहल्ली में स्थित यह केंद्र डिपो स्तर के रखरखाव, भारी ओवरहाल, उपकरण मरम्मत, संरचनात्मक जाँच और एवियोनिक्स उन्नयन का कार्य सँभालेगा।
- ♦ **प्रशिक्षण:**
 - MRO भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिये प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करेगा, घरेलू एयरोस्पेस कौशल को सुदृढ़ करेगा तथा C-130 आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के लिये नए अवसर सृजित करेगा।
- ♦ **तत्परता:**
 - लॉकहीड मार्टिन ने जोर दिया कि यह सुविधा **भारतीय वायु सेना** के 12 C-130J विमानों की निरंतरता और परिचालन तत्परता को बढ़ावा देगी, जिसका व्यापक रूप से सामरिक एयरलिफ्ट तथा मानवीय कार्यों में उपयोग किया जाता है।
- ♦ **साझेदारी:**
 - यह परियोजना दीर्घकालिक भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सात दशकों से अधिक के सहयोग और बढ़ते औद्योगिक सहयोग को दर्शाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ स्वदेशीकरण:

- ⦿ टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने कहा कि MRO केंद्र भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के अनुरूप है तथा 'मेक इन इंडिया' के तहत घरेलू क्षमता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।

❖ सहयोग:

- ⦿ यह सुविधा टाटा-लॉकहीड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड की सफलता पर आधारित है, जिसने हाल ही में अपना 250वाँ C-130J टेल वितरित किया है, जो एक परिपक्व एयरोस्पेस विनिर्माण साझेदारी को रेखांकित करता है।

❖ समय रेखा:

- ⦿ निर्माण कार्य वर्ष 2026 के अंत तक पूरा होने की योजना है और पहला C-130 विमान वर्ष 2027 की शुरुआत में बंगलूरु सुविधा में MRO संचालन के लिये प्रवेश करेगा।

वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन (GELS) 2025

चर्चा में क्यों ?

ओडिशा के पुरी में आयोजित **वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन (GELS) 2025** में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने वैश्विक **स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों** को आकार देने में भारत की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला और इस शिखर सम्मेलन को नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों तथा उद्योग जगत के नेताओं के लिये एक प्रमुख मंच के रूप में स्थापित किया।

मुख्य बिंदु

❖ विज्ञान:

- ⦿ GELS 2025 ने दीर्घकालिक सामुदायिक अभ्यास की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें भारत का विश्वास है कि ओडिशा जैसे राज्य **राष्ट्रीय हरित विकास** और ऊर्जा नवाचार के अगले चरण का नेतृत्व करेंगे।

❖ रिकॉर्ड:

- ⦿ GELS में मंत्री ने भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता में अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि, 31.25 गीगावाट, जिसमें 24.28 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है, की घोषणा की, जो देश की **स्वच्छ ऊर्जा** के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है।

❖ योगदान:

- ⦿ उन्होंने रेखांकित किया कि विश्व ने वर्ष 2024 तक अपनी दूसरी टेरावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़ ली है, जबकि भारत ने अकेले वर्ष 2022-24 के बीच 46 गीगावाट सौर ऊर्जा का योगदान दिया, जिससे वह विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया।

❖ विकास:

- ⦿ GELS ने भारत के परिवर्तनकारी सौर विस्तार को रेखांकित किया, जो 11 वर्षों में 2.8 गीगावाट से बढ़कर लगभग 130 गीगावाट हो गया, जो 4,500% की वृद्धि है, जिससे भारत तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के लिये एक वैश्विक मॉडल बन गया।

❖ संतुलन:

- ⦿ शिखर सम्मेलन में भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी कोयला उपभोक्ता होने की दोहरी चुनौती पर विचार किया गया, साथ ही वैश्विक औद्योगिक और व्यापार परिवर्तनों के बीच प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ क्षमता:

- GELS में ओडिशा की स्वच्छ ऊर्जा प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 3.1 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता है, जो इसकी कुल विद्युत क्षमता का 34% है और राज्य स्तर पर मज़बूत अपनापन दर्शाता है।

❖ पहल:

- शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख घोषणा ओडिशा के लिये **PM सूर्य घर** के तहत 1.5 लाख रूफटॉप सौर ULA मॉडल को स्वीकृति देना था, जिससे 7-8 लाख लोगों, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।
- GELS ने ओडिशा के रूफटॉप सोलर अपनाने पर प्रकाश डाला: 1.6 लाख आवेदन, 23,000 से अधिक इंस्टॉलेशन और 147 करोड़ रुपए की सब्सिडी 19,200 परिवारों को हस्तांतरित की गई, जो मज़बूत कार्यान्वयन को दर्शाता है।

सी. राजगोपालाचारी जयंती

चर्चा में क्यों ?

भारत के **प्रधानमंत्री** ने 10 दिसंबर, 2025 को **चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (राजाजी)** की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम, प्रशासनिक चिंतन तथा सामाजिक सशक्तीकरण में उनके **बहुमूल्य और दूरदर्शी योगदान** को स्मरण किया।



मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** सी. राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर, 1878 को **मद्रास प्रांत** (वर्तमान तमिलनाडु) के सलेम में हुआ था। वर्ष 1899 में उन्होंने विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही सलेम में अपनी वकालत शुरू की।
- ❖ **राजनीतिक तथा सामाजिक सुधार:** राजगोपालाचारी, **लॉर्ड कर्ज़न** द्वारा सांप्रदायिक आधार पर किये जाने वाले बंगाल विभाजन के निर्णय से प्रभावित होने के साथ **लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक** के पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान से प्रेरित हुए।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यह **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)** में शामिल हुए तथा उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- वर्ष 1917 में राजगोपालाचारी सलेम नगर पालिका के अध्यक्ष बने तथा उन्होंने **पिछड़े वर्गों** के सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 1925 में उन्होंने सामाजिक उत्थान हेतु मद्रास प्रांत में एक आश्रम की स्थापना की।
 - ❖ इस आश्रम द्वारा दो पत्रिकाएँ प्रकाशित की गईं- **विमोचनम (तमिल)** और **प्रोहिबिशन (अंग्रेज़ी)**।
- ❖ स्वतंत्रता संग्राम: रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान राजाजी ने चेन्नई, तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व किया।
 - वर्ष 1930 में **दांडी मार्च** के दौरान राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रांत में तिरुचि से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया (जिसे वेदारण्यम सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है)।
 - ❖ वेदारण्यम सत्याग्रह के दौरान उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में एक नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।
 - **भारत छोड़ो आंदोलन** के बाद राजगोपालाचारी के पैम्फलेट “**द वे आउट**” में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच एक अलग मुस्लिम राज्य के संबंध में संवैधानिक गतिरोध को हल करने के क्रम में **सी.आर. फार्मूले** की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
- ❖ मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री: वर्ष 1937 में राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री बने।
 - उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के साथ ज़मींदारी उन्मूलन एवं स्कूलों में हिंदी की शुरुआत सहित अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों को लागू करने में भूमिका निभाई।
 - उन्होंने दलितों के जीवन स्तर को बेहतर करने एवं **सामाजिक समानता** को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।
- ❖ स्वतंत्रता के बाद योगदान: राजगोपालाचारी को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया तथा आगे चलकर वर्ष 1947 में वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल भी बने (वर्ष 1950 में इस पद को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया)।
 - उन्होंने मुस्लिमों को मुख्यधारा में एकीकृत करने के साथ भारत के **पंथनिरपेक्ष स्वरूप** को बनाए रखने की दिशा में कार्य किया।
 - उन्होंने **सरदार पटेल** की मृत्यु के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया तथा **प्रथम पंचवर्षीय योजना** के साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - वर्ष 1959 में राजगोपालाचारी ने बाज़ार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही सरकारी नियंत्रण को कम करने का समर्थन करने के क्रम में **स्वतंत्र पार्टी** का गठन किया।
 - वर्ष 1962 में राजाजी ने अमेरिका में **गांधी पीस फाउंडेशन** के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए **परमाणु परीक्षणों** पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया।
 - **राजगोपालाचारी ने चक्रवर्ती थिरुमगन** (जिसे वर्ष 1958 में **साहित्य अकादमी पुरस्कार** मिला) नाम से रामायण का तमिल में अनुवाद किया।
- ❖ विरासत: सी. राजगोपालाचारी को वर्ष 1954 में ‘**भारत रत्न**’ से सम्मानित किया गया। वे यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे।
- ❖ 25 दिसंबर, 1972 को राजगोपालाचारी का निधन हुआ।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सुजलाम भारत ऐप

चर्चा में क्यों ?

जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है, जो **जल जीवन मिशन (JJM)** के अंतर्गत एक प्रमुख डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य **ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली** का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

- परिचय: सुजल गाँव ID (डिजिटल पहचान) प्रत्येक बस्ती के लिये एक स्पष्ट डिजिटल प्रोफाइल प्रदान करेगी, जिसमें उसके पेयजल स्रोत, बुनियादी ढाँचे की स्थिति, आपूर्ति की विश्वसनीयता, जल की गुणवत्ता और संचालन एवं रखरखाव व्यवस्थाओं का विवरण होगा।
- उद्देश्य: यह मंच ग्राम पंचायतों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) और सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन में पारदर्शिता बढ़ाएगा, साथ ही सामुदायिक भागीदारी तथा निगरानी को प्रोत्साहित करेगा।
- विकास: इसे **भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N)** के सहयोग से विकसित किया गया है।
- एकीकरण: जल नेटवर्क, परिसंपत्ति सूची, जल गुणवत्ता डेटा और सामुदायिक प्रतिक्रिया के सटीक भू-स्थानिक मानचित्रण के लिये इसे **PM गति शक्ति GIS** के साथ एकीकृत किया गया है।
- महत्त्व : इस ऐप को “ग्रामीण जल प्रणालियों के लिये आधार” के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह ग्रामीण जल वितरण प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने में आधार का काम करेगा।

प्राडा द्वारा कोल्हापुरी डील साइन

चर्चा में क्यों ?

इतालवी लग्जरी ब्रांड प्राडा ने लगभग 2,000 जोड़ी कोल्हापुरी चप्पलों का एक सीमित संस्करण संग्रह लॉन्च करने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- भारत में निर्मित: ये सैंडल महाराष्ट्र और कर्नाटक में बनाए जाएंगे, जिनमें पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल को प्राडा के समकालीन डिजाइन के साथ जोड़ा जाएगा।
- कीमत और उपलब्धता: कोल्हापुरी सैंडल की कीमत लगभग 800 यूरो (930 डॉलर) होगी और ये फरवरी से विश्व भर के चुनिंदा प्राडा स्टोर्स के साथ-साथ इसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे।
- उत्पत्ति एवं भूगोल: यह कोल्हापुर (महाराष्ट्र) और आस-पास के जिलों जैसे- सांगली, सतारा और सोलापुर में हस्तनिर्मित है, जो 12वीं-13वीं शताब्दी से संबंधित है तथा मूल रूप से शाही परिवार के लिये तैयार की गई थी।
- कारीगरी: इसे गाय, भैंस या बकरी द्वारा वनस्पति-टैन (vegetable-tanned) चमड़े से निर्मित किया गया है, पूरी तरह से हाथ से निर्मित है, इसमें कील या कृत्रिम घटकों का उपयोग नहीं किया गया है।
- डिजाइन की विशेषताएँ: यह अपने टी-स्ट्रैप आकार, बारीक बुनाई और खुले पंजे वाले डिजाइन के लिये जाना जाता है, जो ज्यादातर टैन या गहरे भूरे रंग में उपलब्ध होता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





- ❖ **भौगोलिक संकेत (GI) का दर्जा:** इसे वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेत (GI) का दर्जा दिया गया था, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के आठ जिले शामिल हैं।
- ❖ **GI टैग विशिष्ट भौगोलिक मूल** वाले उत्पादों की पहचान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उस क्षेत्र के केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही उस नाम का उपयोग कर सकें।

प्रणब मुखर्जी की जयंती

चर्चा में क्यों ?

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति **प्रणब मुखर्जी** की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

प्रमुख बिंदु

- ❖ **प्रारंभिक जीवन:** उनका जन्म 11 दिसंबर, 1935 को **पश्चिम बंगाल के मिराती** में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र थे और भारत की स्वतंत्रता में अपने पिता के योगदान से प्रेरित थे।
- ❖ **शिक्षा और कैरियर:** उन्होंने **कलकत्ता विश्वविद्यालय** से इतिहास, राजनीति विज्ञान और कानून में डिग्री प्राप्त की तथा वर्ष 1969 में राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व एक कॉलेज शिक्षक एवं पत्रकार के रूप में कार्य किया।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ♦ राजनीतिक अनुभव: उन्होंने विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्तमंत्री सहित विभिन्न उच्च पदों पर कार्य किया जिसके साथ ही वे संसद के दोनों सदनों के लिये कई बार निर्वाचित भी हुए।
- ♦ प्रमुख योगदान: उन्होंने वर्ष 2004 से 2012 तक अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सुधारों, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, UIDAI, मेट्रो रेल और अन्य संबंधित नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ♦ कूटनीतिक भूमिका: उन्होंने **IMF**, **विश्व बैंक**, **संयुक्त राष्ट्र महासभा** और राष्ट्रमंडल सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- ♦ राष्ट्रपति पद: पाँच दशकों से अधिक के विशिष्ट राजनीतिक कैरियर के बाद, वे 25 जुलाई, 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति बने।
- ♦ पुरस्कार: उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें वर्ष 2008 में **पद्म विभूषण**, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, 1997 और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट शामिल हैं।
- ♦ प्रकाशन एवं मान्यता: एक विपुल लेखक के रूप में, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक रूप से लेखन किया तथा उन्हें वर्ष 1984 और वर्ष 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्रियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई।

भारत को जूनियर हॉकी में ऐतिहासिक कांस्य पदक

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रमुख बिंदु

- ❖ ऐतिहासिक उपलब्धि: भारत ने जूनियर विश्व कप में पहला कांस्य पदक जीता, यह वर्ष 2016 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद टूर्नामेंट में पहला पदक है।
- ❖ कांस्य पदक मैच: कांस्य पदक मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 0-2 से पीछे छोड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 4-2 से हराया।
- ❖ टूर्नामेंट का फाइनल: जर्मनी ने निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को 3-2 से हराकर अपना आठवाँ जूनियर विश्व कप खिताब जीता।
- ❖ राष्ट्रीय प्रेरणा: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीम के शानदार प्रदर्शन से देश भर के अनगिनत युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी।

राज कुमार गोयल ने CIC पद की शपथ ली

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राज कुमार गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) पद की शपथ ली।

राज कुमार गोयल ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया का स्थान लिया, जिनके पद छोड़ने के बाद यह पद सितंबर 2025 से रिक्त था।

मुख्य बिंदु

- ❖ परिचय: राज कुमार गोयल वर्ष 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे हैं, जो मूल रूप से जम्मू-कश्मीर कैडर के थे। वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद वे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और केंद्रशासित प्रदेश (AG-MUT) कैडर के सदस्य बन गए।
- ❖ अगस्त 2025 में उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्ति ली। अपने कार्यकाल के दौरान गोयल ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण सेवाएँ दीं।
- ❖ सूचना आयुक्तों की नियुक्ति: वर्तमान में आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी सूचना आयुक्त (IC) के पद पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, जया वर्मा सिन्हा, स्वागत दास, संजीव कुमार जिंदल, सुरेंद्र सिंह मीना तथा खुशवंत सिंह सेठी को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग

- ❖ स्थापना: इसकी स्थापना RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय (संवैधानिक निकाय नहीं) के रूप में की गई थी।
- ❖ संरचना: इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं।
- ❖ नियुक्ति: सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

🌀 प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



● लोकसभा में विपक्ष के नेता

● प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

❖ पात्रता और छूट: विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या शासन में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति।

● सांसद, विधायक नहीं होना चाहिये, या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिये।

● किसी राजनीतिक दल से संबद्धता, व्यवसाय या पेशेवर गतिविधि की अनुमति नहीं होती।

● ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

❖ CIC की शक्तियाँ: गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों का निरीक्षण करना, सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना तथा जाँच के लिये समन जारी करना।

❖ कार्य: इसकी प्राथमिक भूमिका RTI अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और नागरिकों के सूचना के अधिकार को बनाए रखना है।

● यह न्यायालय केंद्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं से संबंधित मामलों का समाधान करता है।

भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

भारत 17-19 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो वर्ष 2023 में गांधीनगर, गुजरात में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन पर आधारित है।

मुख्य बिंदु

- ❖ आयोजक: यह सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, ताकि पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य तथा कल्याण पर वैश्विक संवाद को आगे बढ़ाया जा सके।
- ❖ विषय: सम्मेलन का विषय है “लोगों और ग्रह के लिये संतुलन बहाल करना: कल्याण का विज्ञान तथा अभ्यास”, जिसमें न्यायसंगत एवं सतत स्वास्थ्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- ❖ वैश्विक विस्तार: 100 से अधिक देशों के नीति-निर्माता और नेतृत्वकर्ता पारंपरिक चिकित्सा की भविष्य की भूमिका को आकार देने हेतु इसमें भाग लेंगे।
- ❖ उद्देश्य: यह कार्यक्रम पारंपरिक चिकित्सा की प्रासंगिकता को पुनः पुष्टि करने के साथ-साथ इसे विज्ञान, साक्ष्य और ज़िम्मेदार अभ्यास के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने को बढ़ावा देगा।
- ❖ WHO रणनीति: चर्चाएँ WHO की वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-2034 के अनुरूप होगी, जिसका उद्देश्य जन-स्वास्थ्य सेवा और ग्रह कल्याण को बढ़ावा देना है।
- ❖ सामूहिक सत्र: प्रमुख विचार-विमर्श में स्वास्थ्य प्रणालियों में संतुलन पुनर्स्थापित करना, वैज्ञानिक निवेश, शासन, जैवविविधता संरक्षण और स्वदेशी अधिकार शामिल होंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ नवाचार और साक्ष्य: सम्मेलन में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के नैतिक उपयोग के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को जिम्मेदारी से बढ़ावा देने के लिये नवीन दृष्टिकोणों पर जोर दिया जाएगा।
- ❖ विविध मुद्दे: 25 से अधिक सत्रों में **विनियमन, एकीकरण, जैवविविधता संरक्षण** तथा **बौद्धिक संपदा अधिकारों** पर चर्चा की जाएगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

- ❖ **स्थापना:** इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय **ज़िनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में स्थित है।
- ❖ **प्रकार:** यह वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- ❖ **सदस्यता:** जनवरी 2025 तक इसके **194 सदस्य देश** हैं।
- ❖ **उद्देश्य:** WHO का मुख्य उद्देश्य **स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करना और वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की प्रभावी प्रतिक्रिया देना** है।
- ❖ **वर्तमान महानिदेशक:** संगठन के वर्तमान महानिदेशक **डॉ. टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस (2017 से)** हैं।

परमाणु ऊर्जा रूपांतरण विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के **परमाणु ऊर्जा** से संबंधित विधिक ढाँचे के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से **संसद** में सतत परमाणु ऊर्जा दोहन तथा संवर्द्धन विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **नया विधिक ढाँचा:** यह विधेयक परमाणु ऊर्जा के लिये एक व्यापक कानून का प्रस्ताव करता है, जिसके तहत **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962** तथा **परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010** को निरस्त किया जाएगा।
- ❖ **ऊर्जा सुरक्षा:** इसका उद्देश्य परमाणु स्थापित क्षमता का विस्तार करना है, ताकि डेटा सेंटर जैसी भविष्य की आवश्यकताओं के लिये विश्वसनीय, स्वच्छ तथा चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- ❖ **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** यह विधेयक भारत की दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिनमें वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु विद्युत क्षमता का लक्ष्य तथा वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प शामिल है।
- ❖ **निजी भागीदारी:** यह परमाणु ऊर्जा विकास में घरेलू उद्योग तथा निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- ❖ **नियामक तंत्र:** विधेयक **लाइसेंसिंग, सुरक्षा प्राधिकरण, निलंबन तथा निरस्तीकरण** से संबंधित अद्यतन प्रावधान प्रस्तुत करता है, जिससे नियामक निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके।
- ❖ **नागरिक दायित्व:** परमाणु क्षति से संबंधित एक **संशोधित नागरिक दायित्व ढाँचा** प्रस्तावित किया गया है, ताकि सुरक्षा, जवाबदेही और मुआवजा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- ❖ **संस्थागत ढाँचा:** विधेयक में **परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद, दावा आयुक्तों तथा परमाणु क्षति दावा आयोग** जैसे निकायों का प्रावधान किया गया है।
- ❖ **प्रौद्योगिकी विस्तार:** परमाणु ऊर्जा के साथ-साथ विकिरण आधारित प्रौद्योगिकियों को भी एक आधुनिक नियामक संरचना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** समग्र रूप से, यह विधेयक **स्वच्छ ऊर्जा विस्तार**, सुरक्षा तथा जनहित के बीच संतुलन स्थापित करते हुए परमाणु प्रशासन के आधुनिकीकरण की भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

परमाणु ऊर्जा

- ❖ परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है, जो परमाणु के **नाभिक में संचित होती है** और **नाभिकीय अभिक्रियाओं** के परिणामस्वरूप मुक्त होती है।
- ❖ इसका उपयोग **विद्युत उत्पादन, चिकित्सा क्षेत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा परमाणु हथियारों** में किया जाता है।
- ❖ परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत **नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन** हैं।
- ❖ **पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र:** तारापुर, महाराष्ट्र (1969)
- ❖ **सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र:** राजस्थान- अधिकतम परमाणु ऊर्जा उत्पादन
- ❖ **अन्य प्रमुख संयंत्र:** काकरापार (गुजरात), कुडनकुलम और कलपक्कम (तमिलनाडु), नरोरा (उत्तर प्रदेश)
- ❖ **रिएक्टर प्रकार:** PHWR (सर्वाधिक), BWR (तारापुर), फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (कलपक्कम)
- ❖ **ईंधन:** यूरेनियम और थोरियम (भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है)।

रक्षा संपदा दिवस का शताब्दी वर्ष समारोह

चर्चा में क्यों ?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 दिसंबर, 2025 को दिल्ली छावनी स्थित रक्षा संपदा भवन में **रक्षा संपदा दिवस समारोह** की अध्यक्षता की, जो रक्षा संपदा विभाग की **100वीं वर्षगांठ** को चिह्नित करता है

मुख्य बिंदु

- ❖ **समारोह एवं सम्मान:** रक्षा मंत्री द्वारा 61 छावनी बोर्डों में रक्षा भूमि प्रबंधन तथा नगर प्रशासन के क्षेत्र में **सार्वजनिक सेवा** में उत्कृष्ट योगदान के लिये **रक्षा मंत्री पुरस्कार** प्रदान किये गए।
- ❖ **शताब्दी का महत्त्व:** यह आयोजन रक्षा संपदा विभाग की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1765 में बैरकपुर से हुई और 16 दिसंबर, 1926 को इसे औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया।
- ❖ **रक्षा संपदा की भूमिका:** रक्षा मंत्रालय के अधीन यह विभाग **भारत सरकार की सर्वाधिक व्यापक भू-संपत्ति** का प्रबंधन करता है।
- ❖ **डिजिटल परिवर्तन:** ई-छावनी जैसी पहलों के माध्यम से भूमि प्रबंधन का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसके तहत लगभग **20 लाख छावनी निवासियों को 100 प्रतिशत नगरपालिका सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध** कराई जा रही हैं।
- ❖ **पुरस्कार एवं मान्यता:** **जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार** में योगदान के लिये 'जल संचय जन-भागीदारी' श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया।
- ❖ **डिजिटलीकरण:** विरासत में प्राप्त भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे उनका संरक्षण, आसान पुनर्प्राप्ति तथा सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित हुआ है।
- ❖ **रक्षा भूमि प्लेटफॉर्म:** केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर 'रक्षा भूमि' सुरक्षित सर्वरों पर सभी रक्षा भूमि अभिलेखों के एकीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **उन्नत सर्वेक्षण उपकरण:** भूमि की सटीकता तथा प्रबंधन में सुधार के लिये डिफरेंशियल **GPS, GIS** उपकरणों तथा उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जा रहा है।
- ❖ **प्रौद्योगिकी नवाचार:** उपग्रह एवं मानवरहित रिमोट वाहन पहल पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से **AI/ML** तथा उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए अगली पीढ़ी के रक्षा भूमि प्रबंधन समाधान विकसित किये जा रहे हैं।

भारत और ADB के बीच विकास ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार और **एशियाई विकास बैंक (ADB)** ने विभिन्न प्रमुख विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये कुल 2.2 अरब डॉलर से अधिक के **पाँच ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर** किये।

मुख्य बिंदु

- ❖ **क्षेत्रीय प्रभाव:** परियोजनाएँ तीन राज्यों (असम, मेघालय और तमिलनाडु) में फैली हुई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्यों में विकास को बढ़ावा देंगी।
- ❖ **ऋण राशि:** भारत और ADB के बीच 2.2 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- ❖ **आवृत्त परियोजनाएँ:** इनमें **कौशल विकास, रूफटॉप सोलर प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, मेट्रो रेल और इकोटूरिज्म कार्यक्रम** शामिल हैं।
- ❖ **कौशल विकास पहल:** प्रधानमंत्री कौशल एवं रोज़गार क्षमता परिवर्तन के तहत उन्नत ITIs कार्यक्रम का समर्थन करती हैं।
- ❖ **सौर ऊर्जा कार्यक्रम:** **प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY)** के तहत सस्ते और समावेशी रूफटॉप सोलर सिस्टम विकास को गति देने के लिये निधि प्रदान करता है।
- ❖ **स्वास्थ्य परियोजना:** इसमें असम राज्य तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल संवर्द्धन परियोजना (ASTHA) शामिल है।
- ❖ **शहरी परिवहन:** चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना (Tranche 2) का समर्थन करता है।
- ❖ **इकोटूरिज्म एवं आजीविका:** मेघालय में संपूर्ण इकोटूरिज्म और सतत कृषि-आधारित आजीविका विकास के लिये वित्तपोषण प्रदान करता है।
- ❖ **मुख्य कार्यक्रम:** ये ऋण भारत के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों जैसे **नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शहरी अवसंरचना और कौशल विकास** को आगे बढ़ाएंगे।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

- ❖ **स्थापना:** ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी **स्थापना वर्ष 1966** में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- ❖ **मुख्यालय:** मनीला, फिलीपींस
- ❖ **सदस्य:** वर्तमान में इसके **68 सदस्य** हैं, जिनमें से 49 एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के भीतर और 19 अन्य क्षेत्रों से हैं।
- ❖ **उद्देश्य:** आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- ❖ **भारत-ADB:** भारत ADB का **संस्थापक सदस्य** और सबसे बड़े उधारकर्ताओं में से एक है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भू-स्थानिक मिशन पर राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन **भारतीय सर्वेक्षण विभाग** ने 'भू-स्थानिक मिशन: विकसित भारत का एक प्रवर्तक' शीर्षक से भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु

- उद्घाटन एवं स्थल: कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 17 दिसंबर, 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में किया गया।
- उद्देश्य: भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना और राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन को आगे बढ़ाना।
- प्रतिभागी: इसमें नीति-निर्माता, प्रौद्योगिकीविद, उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए।
- घोषणा: राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन (केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित) का उद्देश्य भू-माप संबंधी ढाँचों का आधुनिकीकरण करना, भू-स्थानिक अवसंरचना को बढ़ाना, डेटा का मानकीकरण करना और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना है।
- महत्त्व: यह उन्नत भू-स्थानिक क्षमताओं के माध्यम से **विकसित भारत@ 2047** की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने मार्च 2027 तक भारत में **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (PMBJK)** की संख्या बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्य बिंदु

- वर्तमान स्थिति: 30 नवंबर, 2025 तक संपूर्ण देश में कुल 17,610 **जन औषधि केंद्र (PMBJK)** खोले जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2014 में इनकी संख्या केवल 80 थी, जो इस योजना के महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है।
- लक्ष्य निर्धारित: सरकार ने मार्च 2027 तक **जन औषधि केंद्रों** की संख्या 25,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ताकि कम लागत वाली गुणवत्तापूर्ण **जेनेरिक दवाओं** तक पहुँच और बेहतर हो सके।

जन औषधि केंद्र के बारे में:

- यह सरकार समर्थित रिटेल आउटलेट योजना है, जो सस्ते दामों में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराती है।
- जागरूकता: योजना के तहत बिक्री की बढ़ती मात्रा और उत्पाद शृंखला का विस्तार जनता में जन औषधि दवाओं के प्रति विश्वास एवं जागरूकता को दर्शाता है।
- उद्यमी भागीदारी: जन औषधि केंद्रों की बढ़ती व्यवहार्यता और आकर्षण के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में आउटलेट्स में 37% और MRP बिक्री मूल्य में 38% की वृद्धि हुई।
- आवेदन प्रक्रिया: जन औषधि केंद्रों के लिये आवेदन व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठनों, समितियों, ट्रस्ट, फर्म और कंपनियों से आधिकारिक जन औषधि वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सहकार सारथी

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने **ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCB)** के आधुनिकीकरण और **डिजिटल सशक्तीकरण** के लिये सहकार सारथी नामक साझा सेवा इकाई (SSE) की स्थापना की है।

मुख्य बिंदु

- सहकार सारथी की स्थापना: ग्रामीण सहकारी बैंकों की तकनीकी और सेवा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्वीकृति से सहकार सारथी (SSE) की स्थापना की गई है।
- पंजीकरण की तिथि: सहकारी बैंकिंग के डिजिटलीकरण के लिये साझा अवसंरचना प्रदान करने के उद्देश्य से इस संस्था का पंजीकरण 21 जुलाई, 2025 को किया गया था।
- अधिकृत पूंजी एवं शेयरधारिता: सहकार सारथी की अधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रुपये है, जिसमें **NABARD**, **NCDC** और ग्रामीण सहकारी बैंक समान रूप से 33.33% शेयरधारिता रखते हैं।
- प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: यह साझा आधुनिक बैंकिंग अवसंरचना और डिजिटल सेवाएँ प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं: कॉमन कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS), AEPS और UPI जैसे डिजिटल भुगतान, **साइबर सुरक्षा**, IT गवर्नेंस आदि।
- उद्देश्य और प्रभाव: इस पहल का उद्देश्य RCB को आधुनिक, मानकीकृत और डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना, ग्राहकों तक पहुँच बढ़ाना तथा अन्य विनियमित वित्तीय संस्थानों के समान परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

नमस्ते योजना: सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों का सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

नेशनल एक्शन फॉर मेकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजना के तहत 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया, जिसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSW) की पहचान करना तथा स्वच्छता कार्य में उनकी सुरक्षा एवं गरिमा को सुदृढ़ करना था।

मुख्य बिंदु

- सर्वेक्षण का उद्देश्य:
 - इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नमस्ते योजना के अंतर्गत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSW) की पहचान करना था (न कि **मैनुअल स्कैवेंजर्स**), ताकि बेहतर कार्य परिस्थितियाँ और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकें।
- मृत्यु दर:
 - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के अनुसार, 2019 और अक्तूबर 2025 के बीच खतरनाक सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के कारण 471 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई।
- कानूनी निषेध:
 - मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 7 सीवर या सेप्टिक टैंक में खतरनाक प्रवेश को निषिद्ध करती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ नमस्ते योजना:

- ❶ यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के समन्वय में वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू की गई थी।
- ❷ इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों में मैन्युअल प्रवेश को समाप्त करना, शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना और श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना है।
- ❸ योजना के घटक: इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ERSU) के लिये सुरक्षा उपकरण, मशीनीकृत उपकरणों के लिये पूंजीगत सब्सिडी, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण और खतरनाक सफाई नियंत्रण पर कार्यशालाएँ शामिल हैं।
- ❹ स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (SBM-U) 2.0 के तहत, प्रयुक्त जल प्रबंधन (UWM) घटक मशीनीकरण के माध्यम से खतरनाक सीवर/सेप्टिक टैंक में पानी के प्रवेश को समाप्त करने पर केंद्रित है।

आंध्र प्रदेश में व्हाइट स्पॉट डिज़ीज़

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में मत्स्यपालन क्षेत्र में व्हाइट स्पॉट डिज़ीज़ और अन्य जलीय पशु रोगों की निगरानी एवं नियंत्रण के लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत किये गए उपायों के संबंध में जानकारी दी।

मुख्य बिंदु

- ❖ व्हाइट स्पॉट डिज़ीज़ (WSSV) पुष्टि: आंध्र प्रदेश में फील्ड टीमों ने मत्स्य पालन के नमूने एकत्र किये; निष्क्रिय निगरानी में 4 और सक्रिय निगरानी में 23 नमूनों में व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (WSSV) की पुष्टि हुई।
- ❖ रोग निगरानी कार्यक्रम: PMMSY के तहत 33.78 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय जलीय पशु रोग निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) को देशव्यापी स्तर पर जलीय रोगों का पता लगाने और प्रबंधन के लिये कार्यान्वित किया गया है।
- ❖ नमूना विश्लेषण: नमूनों का विश्लेषण काकीनाडा स्थित राज्य मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (SIFT) में किया जाता है।
- ❖ बीमा सहायता: मत्स्यपालन फसल बीमा योजना के तहत आंध्र प्रदेश के 85 मत्स्यपालकों को कवर किया गया; वर्ष 2025 में 5.21 लाख रुपये के दावों का वितरण किया गया।
- ❖ दिशा-निर्देश: तटीय मत्स्य पालन प्राधिकरण ने WSSV के प्रकोप को रोकने हेतु SPF झींगा/प्रजनन केंद्रों, हैचरी, फार्म, स्वास्थ्य निगरानी और SPF प्रमाणन के दिशा-निर्देश जारी किये।
- ❖ जैव सुरक्षा उपाय: रोगों के प्रसार को सीमित करने के लिये आयातित झींगा प्रजनन स्टॉक का अनिवार्य संगरोध और तटीय मत्स्य पालन प्राधिकरण के साथ झींगा हैचरी एवं फार्मों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया।
- ❖ प्रयोगशाला निगरानी: झींगा और पानी के नमूनों की PCR-आधारित रोग निगरानी रोग का शीघ्र पता लगाने एवं नियंत्रण में सहायक है।
- ❖ वैकल्पिक कृषि प्रणालियाँ: सरकार रोग जोखिम कम करने और जैव सुरक्षा एवं स्थिरता बढ़ाने के लिये बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी (BFT) एवं पुनर्चक्रण मत्स्य पालन प्रणाली (RAS) को बढ़ावा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट, 2025

चर्चा में क्यों ?

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के उद्देश्यों और मुख्य क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

मुख्य बिंदु

- आयोजन: राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये किया गया।
- प्रमुख लक्षित क्षेत्र: इस समिट के मुख्य लक्षित क्षेत्र पर्यटन और आतिथ्य, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित क्षेत्र, वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास, IT/ITeS, मनोरंजन व खेल, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स तथा ऊर्जा थे।
- निवेश रुचि: शिखर सम्मेलन और इसके रोडशो के माध्यम से निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा **4.48 लाख करोड़ रुपये** के समझौता ज्ञापनों, आशय-पत्रों एवं निवेश प्रस्तावों की सामूहिक रुचि व्यक्त की गई।
- निवेशक मंच: यह समिट पूर्वोत्तर भारत को निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने तथा निवेशकों को साझेदारी एवं सहयोग के अवसर प्रदान करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ: क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा पहले जैसे PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, PM कुसुम, सौर पार्क परियोजनाएँ, ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण ((PM JANMAN)), धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) और पूरे पूर्वोत्तर में बायो-गैस संयंत्र स्थापना शामिल हैं।

नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- उद्घाटनकर्ता: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।
- उद्देश्य: सम्मेलन का लक्ष्य भारत की आतंकवाद-रोधी तैयारियों तथा अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करना है।
- आयोजक: सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा किया गया है।
- विज्ञान: यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता विज्ञान से प्रेरित है।
- मुख्य क्षेत्र: प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी साक्ष्य संग्रह, डिजिटल फोरेंसिक, आतंकवाद-रोधी जाँच में डेटा विश्लेषण तथा आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क को बाधित करना शामिल है।
- कट्टरपंथ का सामना: विशेषकर डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से होने वाले कट्टरपंथीकरण और भर्ती प्रक्रियाओं की रोकथाम पर जोर दिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भारत में आतंकवाद से संबंधित ढाँचा

- परिचय: आतंकवाद हिंसा और धमकी का, विशेष रूप से नागरिकों के विरुद्ध, मंशापूर्ण एवं अवैध उपयोग है, जिसका उद्देश्य भय उत्पन्न करना तथा राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य प्राप्त करना है।
- यह भय, व्यवधान और अनिश्चितता का माहौल बनाकर सरकारों या समाजों को प्रभावित करने का ध्येय रखता है।
- भारत आतंकवाद के विरुद्ध 'शून्य सहिष्णुता' की नीति के साथ कठोर रुख रखता है।
- हालाँकि आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, जिससे विशिष्ट गतिविधियों को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है।
- यह अस्पष्टता आतंकवादियों को लाभ पहुँचाती है और कुछ देशों को चुप रहने तथा वैश्विक संस्थाओं में किसी कार्रवाई पर वीटो लगाने में सक्षम बनाती है।

किम्बर्ले प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा भारत

चर्चा में क्यों ?

भारत को 1 जनवरी, 2026 से किम्बर्ले प्रक्रिया (Kimberley Process- KP) की अध्यक्षता करने के लिये चयनित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- किम्बर्ले प्रक्रिया:
 - किम्बर्ले प्रक्रिया (Kimberley Process) हीरों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय पहल है।
 - यह ऐसे हीरों के व्यापार पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया है जिनका इस्तेमाल विद्रोही गुटों द्वारा चुनी हुई सरकारों के खिलाफ संघर्ष एवं युद्ध के वित्तपोषण के लिये किया जाता है।
- त्रिपक्षीय संरचना:
 - किम्बर्ले प्रक्रिया सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज संगठनों की एक संयुक्त पहल है।
- मुख्यालय:
 - इसका कोई औपचारिक संगठन नहीं है; इसका संचालन सदस्य देशों तथा बारी-बारी से अध्यक्षता करने वाले देशों के माध्यम से किया जाता है।
- प्रमाणन योजना:
 - किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जनादेश के अंतर्गत 1 जनवरी, 2003 से लागू किया गया।
- वैश्विक कवरेज:
 - किम्बर्ले प्रक्रिया में यूरोपीय संघ एवं उसके सदस्य देशों सहित कुल 60 प्रतिभागी सम्मिलित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ भारत की भूमिका:

- यह तीसरी बार है (2008, 2019 और 2026) जब भारत को इसके नेतृत्व की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

वीर बाल दिवस

चर्चा में क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा युवा नायकों की बहादुरी और उनके आदर्श मूल्यों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 26 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया गया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **वीर बाल दिवस:** यह दिवस साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिये मनाया जाता है अर्थात् गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की स्मृति में, जिन्होंने वर्ष 1705 में जबरन धर्मांतरण के विरोध में शहादत प्राप्त की थी।
- ❖ **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार:** भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, पर्यावरण और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिये बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया।
- ❖ **पुरस्कार विजेता:** इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 20 बच्चों को इस पुरस्कार के लिये चयनित किया गया।
- ❖ **समारोह का विवरण:** पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

गुरु गोविंद सिंह:

❖ परिचय:

- दस सिख गुरुओं में से अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर, 1666 को पटना, बिहार में हुआ था।
- उनकी जयंती नानकशाही कैलेंडर पर आधारित है।
- गुरु गोविंद सिंह अपने पिता 'गुरु तेग बहादुर' यानी नौवें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने।
- वर्ष 1708 में उनकी हत्या कर दी गई थी।

अगरबत्ती के लिये नया BIS मानक

चर्चा में क्यों ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अगरबत्ती के लिये नया BIS मानक जारी किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **मानक:** IS 19412:2025 - अगरबत्ती (Incense Sticks), जिसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा विकसित किया गया है।
- ❖ **भारतीय मानक ब्यूरो:**
 - यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत हुई थी। BIS गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के निर्धारण तथा प्रमाणन के लिये ज़िम्मेदार है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ उपभोक्ता विश्वास: IS 19412:2025 के अनुरूप उत्पाद **BIS मानक चिह्न** धारण करने के पात्र होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित, परीक्षित और गुणवत्ता-सुनिश्चित अगरबत्तियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।
- ❖ निषिद्ध पदार्थ: यह मानक एलेथ्रिन, परमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोनिल जैसे कीटनाशक रसायनों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- ❖ उत्पाद: यह मानक मशीन से निर्मित, हाथ से निर्मित और पारंपरिक मसाला अगरबत्तियों पर लागू होता है, जिसमें कच्चे माल, जलने की गुणवत्ता, सुगंध प्रदर्शन तथा अनुमेय रासायनिक सीमाओं के लिये मानदंड निर्धारित किये गए हैं।

FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025** में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हंपी को हार्दिक बधाई दी।

मुख्य बिंदु

- ❖ स्थल: यह चैंपियनशिप दोहा, कतर में आयोजित की गई।
- ❖ पदक विजेता: अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हंपी।
 - ⦿ अर्जुन एरिगैसी ने पुरुष वर्ग में और कोनेरू हंपी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया।
- ❖ FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025: इस चैंपियनशिप में 13-चरणीय स्विस् प्रणाली प्रारूप के अंतर्गत रैपिड समय-नियंत्रण अपनाया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों की उच्च गति में निर्णय क्षमता और कौशल की परीक्षा होती है।
 - ⦿ स्वर्ण पदक (पुरुष वर्ग): मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे)।
 - ⦿ स्वर्ण पदक (महिला वर्ग): जू वेनजुन (चीन)।

के-4 बैलिस्टिक मिसाइल

चर्चा में क्यों ?

भारत ने परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों से 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे की मारक क्षमता वाली के-4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ प्रक्षेपण मंच: यह प्रक्षेपण भारतीय नौसेना की परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) INS अरिघाट से बंगाल की खाड़ी में किया गया।
- ❖ सामरिक महत्त्व: यह परीक्षण भारत की समुद्र-आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करता है तथा देश की परमाणु त्रय (Nuclear Triad)- भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हथियारों की तैनाती की क्षमता, को मजबूती प्रदान करता है।
- ❖ द्वितीय-हमला क्षमता: के-4 मिसाइल का यह सफल परीक्षण भारत की द्वितीय-हमला क्षमता को सशक्त बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी प्रारंभिक परमाणु हमले के पश्चात भी भारत प्रभावी एवं निर्णायक प्रत्युत्तर देने में सक्षम रहेगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **DRDO की भूमिका:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित के-4 मिसाइल ठोस ईंधन तकनीक एवं उन्नत नेविगेशन प्रणालियों से युक्त है, जो इसकी विश्वसनीयता तथा सटीकता को बढ़ाती है।
- ❖ **बैलिस्टिक मिसाइलों की विशेषताएँ:**
 - ⦿ बैलिस्टिक मिसाइलें रॉकेट द्वारा संचालित हथियार प्रणालियाँ होती हैं, जो प्रक्षेपण के बाद मुख्यतः मुक्त-पतन पथ का अनुसरण करती हैं। ये पारंपरिक या परमाणु युद्धक ले जाने में सक्षम होती हैं और इन्हें भूमि, समुद्र या वायु से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- ❖ **मारक क्षमता के आधार पर वर्गीकरण:**
 - ⦿ छोटी दूरी की मिसाइलें: 1,000 किमी से कम
 - ⦿ मध्यम दूरी की मिसाइलें: 1,000–3,000 किमी
 - ⦿ मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलें: 3,000–5,500 किमी
 - ⦿ लंबी दूरी/अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM): 5,500 किमी से अधिक
- ❖ **अग्नि-V:**
 - ⦿ अग्नि-V भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली एक ICBM मिसाइल है।

भारत टैक्सी पहल

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने 'भारत टैक्सी' नामक अपनी तरह की पहली ड्राइवर-स्वामित्व वाली सहकारी राइड-हेलिंग पहल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य निजी टैक्सी एग्रीगेटरों के विकल्प के रूप में निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **भारत टैक्सी:** यह सरकार समर्थित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे एक सहकारी मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ ड्राइवर पारंपरिक निजी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय शेयरधारक और सह-मालिक होते हैं।
- ❖ **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य टैक्सी चालकों को उचित आय सुनिश्चित करके सशक्त बनाना, निजी एग्रीगेटरों (जैसे ओला और उबर) पर निर्भरता कम करना तथा यात्रियों को किफायती, पारदर्शी परिवहन सेवाएँ प्रदान करना है।
- ❖ **सहकारी संरचना:** यह सेवा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है।
- ❖ **लॉन्च:** यह सेवा 1 जनवरी, 2026 से पूरे देश में शुरू होने वाली है।
- ❖ **ड्राइवर के लिये लाभ:** ड्राइवर के स्वामित्व वाला मॉडल, कोई कमीशन नहीं और लाभ साझाकरण।
- ❖ **यात्रियों के लिये लाभ:** पारदर्शी मूल्य निर्धारण, किफायती यात्राएँ और अनेक वाहन विकल्प।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

